https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'लोकंतत्र हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है'

वर्ष-13, अंक-04 16-28 फरवरी, 2018 (पाक्षिक) ₹20

बजट 2018-19

अंत्योदय की ओर...

गांव, गरीब, किसानोन्मुखी बजट

125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला बजट

हमने पारदर्शी, निर्णायक और संवेदनशील सरकार चलाई है: अमित शाह

मैसूर में 'परिवर्तन यात्रा' रैली के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते कर्नाटक प्रदेश भाजपा नेतागण

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

भाजपा मुख्यालय में संत रविदास जयंती के मौके पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते श्री अमित शाह

गुरु गोविंद सिंह के 350वें जयंती के अवसर पर चांदनी चौक, नई दिल्ली में आयोजित 'सरबंसदानी' को संबोधित करते श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

गांव, गरीब, किसानोन्मुखी बजट

06

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2018-19 प्रस्तुत किया। इस बजट में उन्होंने गांव, गरीब, किसानों, महिलाओं के हितों को ध्यान तो रखा ही, साथ ही उनके जीवन को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। श्री जेटली ने गरीबों के लिए...

वैचारिकी

निर्माण के लिए एकसूत्रता चाहिए 21

श्रद्धांजलि

चिंतामन वनगा / हुकुम सिंह 23

बजट सत्र

लोकंतत्र हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है: नरेंद्र मोदी 24

हमने पारदर्शी, निर्णायक और संवेदनशील सरकार चलाई है: अमित शाह 26

वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2017-18 में 6.75 प्रतिशत होने... 30

अन्य

कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य पर जोर 10

125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला बजट: नरेंद्र मोदी 12

सर्वांगीण विकास को समर्पित बजट : अमित शाह 13

2017-18 के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर पिछले छह सालों में सबसे कम 19

मुक्त, सर्वसमावेशी और नियम आधारित क्षेत्रीय संरचना के... 28

हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास के आदर्शों का अनुसरण करना... 31

मन की बात 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

15 कर्नाटक में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 फरवरी को बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी द्वारा...

17 सिद्धारमैया सरकार भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण और दमनकारी है: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार को भ्रष्ट...

सरकार की उपलब्धियां

18 जीएसटी के पहले आठ महीने में अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार के कुशल...

20 सेवा क्षेत्र की विकास दर 8.3 प्रतिशत

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 55.2...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

लोकतंत्र भारत की परंपरा में है। यह हज़ारों सालों से हमारे लोकाचार का एक हिस्सा है। किसी भी भारतीय को लोकतंत्र का पाठ कांग्रेस से सीखने की ज़रूरत नहीं है, जिसने हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को बार-बार छिन्न-भिन्न किया है।

@AmitShah

GST को गब्बर सिंह टैक्स बोलने वालों से यह देश जरूर पूछेगा कि One Rank - One Pension में जवान के एकाउंट में पैसा भेजना, शहीद की विधवा के एकाउंट में पैसा भेजना, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस देना, सौभाग्य योजना से गरीब के घर में बिजली देना..... यह डकैती है क्या?

@PiyushGoyal

रेलवे के कांट्रेक्ट वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिये डेटाबेस तैयार होगा, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी, मेडिकल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन और सैलरी की डिटेल होगी, इस से कांट्रेक्ट वर्कर्स के सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता आयेगी।

facebook

आमजन को घर के पास ही विभिन्न तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई ई-मित्र योजना व्यवस्था में पारदर्शिता और तेजी लाने हेतु एक ई-शासन रूपी पहल है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक ही छत के नीचे सभी विभागों के लाभ जैसे बिजली, पानी, मोबाइल के बिल जमा करवाने से लेकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास, विभिन्न परीक्षाओं की फीस, विवाह प्रमाण पत्र, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेन्ट, रोज़गार आवेदन जैसी अनेक सेवाएं कुशल, सुविधाजनक और मैत्रीपूर्ण तरीके से उपलब्ध करवाना है। — **वसुंधरा राजे**

मध्यप्रदेश की धरती से अन्न रूपी सोना उपजाने वाले हर किसान भाई के साथ मैं खड़ा हूं। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे प्रिय किसान भाइयों मैं भी एक कृषक हूं और जानता हूं कि अच्छी उपज के बाद उसका सही मूल्य मिलना भी आवश्यक है। आपकी फसलों का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए आप भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराएं और इसका लाभ लें। — **शिवराज सिंह चौहान**

भारत सरकार की 'मेक इन इण्डिया' के अनुरूप, प्रदेश सरकार भी 'मेक इन यू.पी.' को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि देश में विनिर्माण के क्षेत्र में होने वाला अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में आये।

— **योगी आदित्यनाथ**

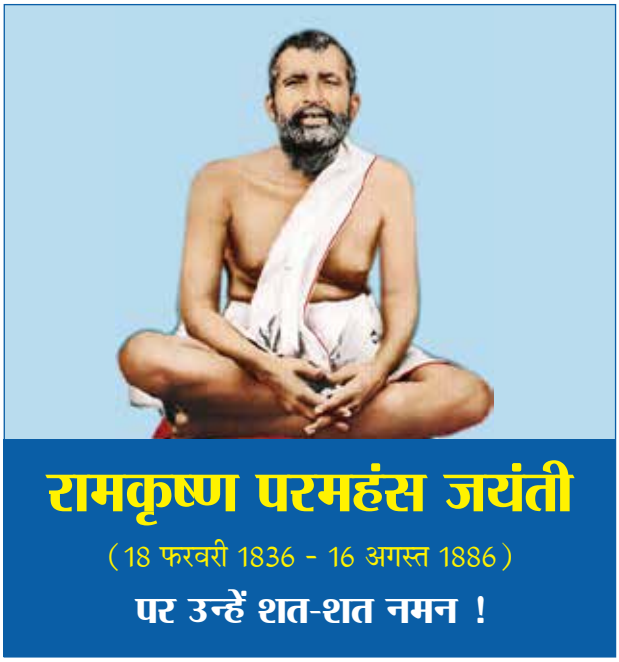

'ईज ऑफ लिविंग' सपने को साकार करता बजट

संसद में 2018–19 के बजट प्रस्तुत होने के साथ पुनः एक बार विकसित, समृद्ध एवं वैभवपूर्ण भारत का संकल्प मजबूत हुआ है। समाज के वंचित वर्गों के साथ–साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को बजट में प्राथमिकता दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सबके बावजूद बजटीय घाटा एवं वित्तीय अनुशासन पर लगाम ढीली नहीं छोड़ी गई है। सही मायनों में देखा जाए तो यह एक संपूर्ण बजट है, जिसमें अंत्योदय के सिद्धांतों के अनुरूप गरीब से गरीब व्यक्ति को योजनाओं के केन्द्र में रखते हुए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला, सौभाग्य तथा स्वच्छता मिशन जैसी योजनाओं के लिए भरपूर वित्तीय प्रावधान करके हर घर को गैस कनेक्शन, बिजली एवं शौचालय देने के इरादे को मजबूत किया गया है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर जोर देते हुए उनको भविष्योन्मुखी लक्ष्यों के अनुरूप सुदृढ़ करके देश के ग्रामीण एवं शहर के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की गई है।

यह बजट पूर्व के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए किसान, गरीब एवं गांव की प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र को अपने केन्द्र में लिये हुए है। लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से कृषि क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन आयेगा, जिससे किसानों के जीवन में भारी बदलाव होगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ होगा। प्रधानमंत्री के 'न्यू इंडिया' के कार्यक्रम में किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य है, जो इस घोषणा के बाद इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इसके अलावा किसानों के लिए अन्य नये बजटीय प्रावधानों से मत्स्य पालन, पशुपालन, बांस तथा अन्य कृषि कार्य में जबरदस्त तेजी आने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी घोषणा थी वह स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित रही जिसके अंतर्गत देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम मानी जाने वाली इस योजना में 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। सरकार के लिये शुरू से ही स्वास्थ्य एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है तथा अब तक दवा, स्टेंट, घुटना का आपरेशन, डायलेसिस सुविधा और कई अन्य स्वास्थ्य सुविधायें, जो देश के एक बड़े वर्ग की पहुंच से बाहर थीं, अब इस वर्ग को सुलभ हुई हैं। नये मेडिकल कॉलेजों को खोलने के निर्णय से स्वास्थ्य की आधारभूत व्यवस्था सुदृढ़ होगी और जन–जन तक स्वास्थ्य सुविधायें अब पहुंच पायेंगी।

> यह बजट 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म' की नीति का अनुसरण करते हुए 'सबका साथ, सबका विकास' के विचारों से अभिमंत्रित है। इस बजट को ठीक ही 'भारत का बजट' कहा जा रहा है, क्योंकि यह ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास के साथ ही विकसित, सुदृढ़ एवं समृद्ध भारत के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है।

बजट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वित्तीय अनुशासन को बनाते हुए बजटीय घाटा जो इस बार 3.5 प्रतिशत रहा, उसे 3.3 प्रतिशत तक नीचे लाने को कटिबद्ध है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई तरह के ढांचागत सुधारों से देश उच्च विकास दर के दौर में प्रवेश कर जायेगा। कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर घरेलू उद्योगों के लिये बजट में सरकार ने नए अवसर पैदा किए हैं, जिससे देश में रोजगार की संभावनाएं निश्चित रूप से बढेंगी तथा 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं को बल मिलेगा। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों, लघु एवं मध्यम उद्योगों, ऊर्जा, रेलवे तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में परिवर्तनकारी प्रावधान किये गए हैं। इससे पूरी अर्थव्यवस्था को भारी गति मिलेगी तथा उच्च विकास दर प्राप्त करने में सहायक होगी।

यह बजट प्रधानमंत्री के विचारों को परिलक्षित करता है जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार किसान, गरीब, महिला, युवा एवं अनु. जाति एवं जनजाति के हितों के लिये प्रतिबद्ध रही। साथ ही यह 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म' की नीति का अनुसरण करते हुए 'सबका साथ, सबका विकास' के विचारों से अभिमंत्रित है। इस बजट को ठीक ही 'भारत का बजट' कहा जा रहा है, क्योंकि यह ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास के साथ ही विकसित, सुदृढ़ एवं समृद्ध भारत के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा वित्त मंत्री अरुण जेटली वास्तव में इस बजट के लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक जिम्मेदार, जवाबदेह और पारदर्शी राजनैतिक संस्कृति की शुरुआत की है। जैसाकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बजट गरीबों की आकांक्षाओं को नया पंख लगा रहा है, यह बजट गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' के सपने को साकार करता है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

गांव, गरीब, किसानोन्मुखी बजट

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना, 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2018-19 प्रस्तुत किया। इस बजट में उन्होंने गांव, गरीब, किसानों, महिलाओं के हितों को ध्यान तो रखा ही, साथ ही उनके जीवन को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। श्री जेटली ने गरीबों के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव किया, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया और अवसंरचना विकास के लिए छह लाख करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया।

किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2018-19 पेश किया। बजट पेश करते हुए श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आजादी के 75वें साल में अर्थात् वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का आह्वान किया है। श्री जेटली कहा कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। हम कृषि को एक उद्यम मानते हैं और किसानों की मदद करना चाहते हैं, ताकि वे कम खर्च करके समान भूमि पर कहीं ज्यादा उपज सुनिश्चित कर सकें और उसके साथ ही अपनी उपज की बेहतर कीमतें भी प्राप्त कर सकें।

श्री जेटली ने यह घोषणा करते हुए काफी प्रसन्नता जाहिर की कि सरकार ने अब तक अघोषित सभी खरीफ फसलों के लिए उत्पादन लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने का निर्णय लिया है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशविरा कर नीति आयोग एक अचूक व्यवस्था कायम करेगा, जिससे कि किसानों को उनकी उपज की पर्याप्त कीमत मिल सके।

एक अहम कदम के रूप में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण को वर्ष 2017-18 के 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की। सरकार के विज़न को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2018-19 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'ऑपरेशन ग्रीन्स' लांच करने की घोषणा की, ताकि जल्द नष्ट होने वाली जिन्सों जैसे कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटा जा सके। 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर शुरू किया गया 'ऑपरेशन ग्रीन्स' इस क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और प्रोफेशनल प्रबंधन को बढ़ावा देगा। श्री जेटली ने 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को होने वाले लाभों के संदर्भ में पांच वर्षों की अवधि तक 100 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष

2018-19 से होगी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कटाई उपरांत मूल्य संवर्द्धन में प्रोफेशनल नजरिए को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा श्री जेटली ने यह जानकारी दी कि सरकार ने बड़े पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। बड़े क्लस्टरों, विशेषकर प्रत्येक 1000 हेक्टेयर में फैले क्लस्टरों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण उत्पादक संगठनों (वीपीओ) में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत क्लस्टरों में जैविक खेती करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि अत्यंत विशिष्ट औषध एवं सुगंधित पौधों की संगठित खेती में सहायता करने और इत्र, आवश्यक तेलों तथा अन्य संबंधित उत्पादों का उत्पादन करने वाले छोटे एवं कुटीर उद्योगों की मदद करने के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में 86 प्रतिशत से भी अधिक छोटे एवं सीमांत किसान हैं, जो सीधे एपीएमसी और अन्य थोक बाजारों में लेन-देन करने की स्थिति में हमेशा नहीं होते हैं। इन 'ग्रामों' में मनरेगा तथा अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ई-नाम से जोड़ा जाएगा तथा एपीएमसी के नियमन के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि इससे किसान सीधे उपभोक्ताओं और व्यापक खरीदारी करने वालों को अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे।

श्री जेटली ने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने ई-नाम को मजबूत करने और 585 एपीएमसी में ई-नाम की कवरेज बढ़ाने की घोषणा की थी। इनमें से 470 एपीएमसी को ई-नाम नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और शेष एपीएमसी को मार्च 2018 तक इससे जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन से संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि वाला कृषि-बाजार ढांचागत कोष बनाया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 715 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से दोगुना कर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 1400 करोड़ रुपये करने की घोषणा करते हुए श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने वाला हमारा प्रमुख कार्यक्रम है और यह क्षेत्र औसतन 8 प्रतिशत सालाना की दर से आगे बढ़ रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर सरकार इस क्षेत्र में विशिष्ट कृषि-प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी और सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करेगी।

मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों की पूर्ति में मदद के लिए एक प्रमुख कदम की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) की सुविधा इस क्षेत्र को भी देने की बात कही। इससे पशु, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी एवं मत्स्य पालन के लिए फसल ऋण और ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो अब तक केसीसी के तहत केवल कृषि क्षेत्र को ही उपलब्ध था। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि बुनियादी ढांचागत विकास कोष (एफएआईडीएफ) और पशुपालन क्षेत्र की ढांचागत जरूरतों के वित्तपोषण के लिए पशुपालन बुनियादी ढांचागत विकास कोष (एएचआईडीएफ) बनाने की भी घोषणा की।

श्री जेटली ने बांस को 'हरित सोना' की संज्ञा देते हुए 1290 करोड़ रुपये के पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन लांच करने की घोषणा की, जो पूर्ण बांस मूल्य श्रृंखला के मार्ग की बाधाएं दूर करने और समग्र रूप से बांस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर से जुड़ी अवधारणा पर आधारित है। बांस उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने, संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए सुविधाओं के सृजन, एमएसएमई, कौशल निर्माण और ब्रांड निर्माण पर फोकस होने की बदौलत यह घोषणा किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने में अहम योगदान देगी।

श्री जेटली ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के प्रयासों में आवश्यक मदद देने और खेत में ही फसल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए एक विशेष योजना क्रियान्वित की जाएगी।

सरकार ने बड़े पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। बड़े क्लस्टरों, विशेषकर प्रत्येक 1000 हेक्टेयर में फैले क्लस्टरों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण उत्पादक संगठनों (वीपीओ) में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत क्लस्टरों में जैविक खेती करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

बजट में कर–राहत से 99 प्रतिशत छोटे उद्यमों को फायदा

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट में उन कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत के घटे हुए दर का प्रस्ताव किया, जिनका वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है। यह सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों के पूरे संवर्ग को फायदा पहुंचाएगा। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाली 99 प्रतिशत कंपनियां इसी संवर्ग में आती हैं। वित्त मंत्री ने कहा, 'चरणबद्ध तरीके से कॉरपोरेट टैक्स में कमी लाने के मेरे वायदे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है।' कॉरपोरेट टैक्स की निम्न दर से 99 प्रतिशत कंपनियों को फायदा होगा। उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त धन होगा। इससे रोजगार के नये मौके बनेंगे।

वित्त मंत्री ने आम बजट 2017 को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को कम करके 25 प्रतिशत तक लाने की घोषणा की थी। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाली कुल कंपनियों में से 96 प्रतिशत कंपनियों को इससे फायदा हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि इस निर्णय के पश्चात रिटर्न दाखिल करने वाली कुल 7 लाख कंपनियों में से 7000 कंपनियां ऐसी होंगी, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक होगा और वे 30 प्रतिशत के कर दायरे में आएंगी।

ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जीविका के साधनों के सृजन के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए घोषणा की कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के साधन, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर सरकार और अधिक धन राशि खर्च करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि खेती से जुड़े कार्यकलापों और स्व-रोजगार के कारण रोजगार के अलावा, इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अलावा 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे।

'प्रधानमंत्री कृषि योजना'– हर खेत को पानी के अंतर्गत भू-जल सिंचाई योजना को मजबूत बनाने के लिए यह सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू होगी इसके लिए 2600 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं की स्व-सहायता समूह को ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपये किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को आशा है कि मार्च 2019 तक स्व-सहायता समूहों की ऋण राशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आबंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपये किया गया है।

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत: 40,000 रुपए की मानक कटौती

2.5 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत देने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि परिवहन भत्ता और विविध चिकित्सा व्ययों के संदर्भ में वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि दिव्यांगजनों को बढ़े दर पर मिलने वाला परिवहन भत्ता जारी रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि मानक कटौती से पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, जो सामान्यतया परिवहन और चिकित्सा व्यय के कारण भत्ते का लाभ नहीं ले पाते। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। इस निर्णय से लाभांवित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

श्री जेटली ने कहा, 'सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत आय कर के दर-ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूं। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों

देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के साधन, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर सरकार और अधिक धन राशि खर्च करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

की आय बेहतर होती है।'

बुनियादी क्षेत्र के आबंटन में 5.97 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि

सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रमुख संवाहक की भूमिका की पहचान करते हुए आम बजट 2018-19 में बुनियादी ढांचे के आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की। इस क्षेत्र के लिए बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्ययों को 2017-18 के 4.94 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 5.97 करोड़ रुपए कर दिया है। 2018-19 में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,34,572 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक आबंटन किया गया, जबकि आपदा से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 60 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया।

शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकार ने समग्र बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के माध्यम से 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 100 आदर्श स्मारकों का भी उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के अन्तर्गत किए गए कार्यों की सराहना करते हुए जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2.04 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 99 शहरों का चयन किया गया है। 2350 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है और 20,852 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपए की राज्य स्तरीय योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। 19,428 करोड़ रुपए मूल्य की 494 परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति अनुबंध और 12,429 करोड़ रुपए की लागत की 272 परियोजनाओं के लिए सीवर कार्यों के लिए अनुबंध प्रदान कर दिए गए हैं। 482 शहरों ने क्रेडिट रेटिंग प्रारंभ कर दी है और 144 शहरों को निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हो चुकी है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अलावा वित्तीय बुनियादी परियोजनाओं में मदद के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को मदद प्रदान करेगा। सड़क क्षेत्र में हाल ही में स्वीकृत भारतमाला परियोजना का उद्देश्य प्रथम चरण में 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 35 हजार किलोमीटर राजमार्ग को विकसित करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विशेष उद्देश्य वाहनों और टोल, संचालन एवं स्थानांतरण (टीओटी) एवं बुनियादी निवेश कोष जैसे अभिनव ढांचों के उपयोग को अपनी सड़क परिसंपत्तियों में शामिल करने पर विचार करेगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों पर संपर्क में वृद्धि के क्रम में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार सेला पास के अंतर्गत सुरंग का निर्माण कराएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सी-प्लेन गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।

नागर विमानन क्षेत्र में, बजट 2018-19 में हवाई अड्डा क्षमता में पांच गुना विस्तार के लिए एक वर्ष में एक बिलियन आवाजाही को नियंत्रित करने हेतु एक नवीन पहल नाभ निर्माण की घोषणा की गई है। इस विस्तार को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की दृढ़ बैलेंसशीट के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। घरेलू हवाई यात्री परिवहन में प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के माध्यम से देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हैलीपैडों को जोड़ा जाएगा, जहां अभी सेवाएं नहीं है। 16 हवाई अड्डों पर संचालन पहले से ही प्रारंभ किए जा चुके हैं।

डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आम बजट 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 3073 करोड़ रुपए के दोहरे आबंटन की घोषणा की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम गुप्तचर, डिजिटल बुनियादी ढांचे, व्यापक डाटा विश्लेषण और संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल के लिए अनुसंधान हेतु उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना में सहायता के लिए साइबर भौतिक प्रणालियों पर एक अभियान का शुभारंभ करेगा।

डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आम बजट 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 3073 करोड़ रुपए के दोहरे आबंटन की घोषणा की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम गुप्तचर, डिजिटल बुनियादी ढांचे, व्यापक डाटा विश्लेषण और संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल के लिए अनुसंधान हेतु उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना में सहायता के लिए साइबर भौतिक प्रणालियों पर एक अभियान का शुभारंभ करेगा।

दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के लिए बजट 2018-19 में 10 हजार करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सरकार ने 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक ब्राडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए 5 लाख वाई-फाई स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि भारत नेट परियोजना के प्रथम चरण में 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को ब्राडबैंड सुविधा से समर्थ बना दिया गया है।

श्री जेटली ने यह भी घोषणा की कि नीति आयोग कृत्रिम गुप्तचर के क्षेत्र में सीधे प्रयासों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहल करेगा। उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के लाभ को प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग आईआईटी चेन्नई में एक स्वदेशी 5जी टेस्ट बैड की स्थापना में मदद प्रदान करेगा। ■

बजट 2018-19 की मुख्य बातें

कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य पर जोर

- आम बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के मिशन पर फोकस।
- सरकार ने कहा, अनेक ढांचागत सुधारों की बदौलत भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएगा। विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्रों में विकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 8 प्रतिशत से भी अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करने की दिशा में मजबूती से अग्रसर हो गया है।
- अधिकतर रबी फसलों की ही तरह सभी अघोषित खरीफ फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगी; कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण वर्ष 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये।
- 86 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित एवं उन्नत किया जाएगा।
- किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन्स' लांच किया गया।
- मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष की घोषणा; पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1,290 करोड़ रुपये का आवंटन।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली ऋण राशि को पिछले साल के 42,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 75,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।

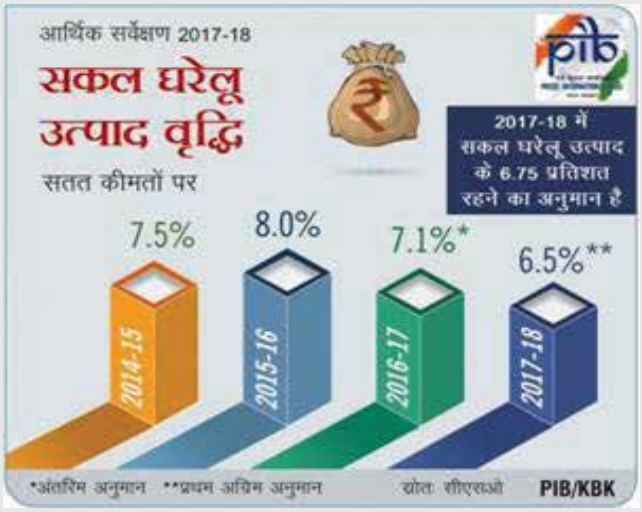

- निम्न एवं मध्यम वर्ग को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उज्ज्वला, सौभाग्य और स्वच्छ मिशन के लिए अधिक लक्ष्य तय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिए परिव्यय 1.38 लाख करोड़ रुपये होगा। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 तक हर जनजातीय ब्लॉक में एकलव्य आवासीय स्कूल होगा। अनुसूचित जातियों के लोगों से जुड़े कल्याण कोष को बढ़ावा मिला।
- द्वितीयक एवं तृतीयक इलाज के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की सीमा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई है, जिसके दायरे में 10 करोड़ से भी अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को लाया जाएगा।
- राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तय किया गया, यह 2018-19 में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
- 10 प्रमुख स्थलों को प्रतीक पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा।
- रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इत्यादि पर उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- विनिवेश 72,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर 1,00,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा।
- पीली धातु को एक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में विकसित करने के लिए

व्यापक स्वर्ण नीति बनाने की तैयारी।

- 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्राप्त लाभ पर 2018-19 से लेकर पांच वर्षों तक 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव।
- धारा 80-जेजेएए के तहत नए कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले कुल वेतन पर 30 प्रतिशत कटौती में ढील देकर इसे फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के लिए 150 दिन किया जाएगा, ताकि ज्यादा रोजगार सृजित हो सके।
- ऐसी अचल संपत्ति में लेन-देन के संबंध में कोई समायोजन नहीं होगा, जिसमें सर्किल रेट मूल्य कुल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 50 करोड़ रुपये से कम के कारोबार (वित्त वर्ष 2015-16 में) वाली कंपनियों के लिए फिलहाल उपलब्ध 25 प्रतिशत की घटी हुई दर का लाभ वित्त वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार की जानकारी देने वाली कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हो सकें।
- परिवहन भत्ते के लिए मौजूदा छूट और विविध चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के स्थान पर 40,000 रुपये की मानक कटौती। इससे 2.5 करोड़ नौकरीपेशा कर्मचारी एवं पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों को प्रस्तावित राहत
- बैंकों और डाकघरों में जमाराशियों पर ब्याज आमदनी संबंधी छूट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी।
- धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं। सभी सावधि जमा योजनाओं और आवर्ती जमा योजनाओं के तहत प्राप्त ब्याज पर भी लाभ मिलेगा।
- धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और/अथवा चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
- धारा 80डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर चिकित्सा व्यय

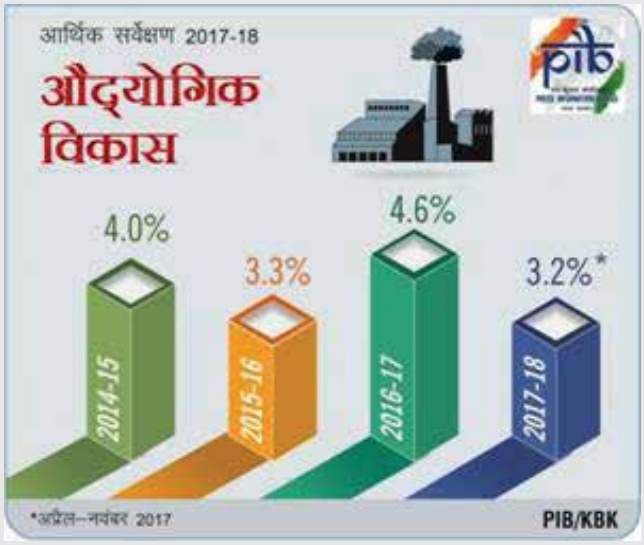

के लिए कटौती सीमा 60,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80,000 रुपये (अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है।

- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। वर्तमान निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में अवस्थित स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार को बढ़ावा देने हेतु आईएफएससी के लिए और अधिक रियायतें।
- कैश इकॉनोमी को नियंत्रण में रखने के लिए ट्रस्टों और संस्थानों को 10,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी और इस पर टैक्स लगेगा।
- 1 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा, जिसमें कोई भी सूचीकरण लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, 31 जनवरी, 2018 तक हुए सभी लाभ को संरक्षित किया जाएगा।
- इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव।
- व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेशन टैक्स पर देय उपकर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह में और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपसी संपर्क लगभग पूरी तरह समाप्त करने के लिए देश भर में ई-निर्धारण शुरू करने का प्रस्ताव।
- देश में और ज्यादा रोजगारों के सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों के कलपुर्जों, फुटवियर और फर्नीचर में 'मेक इन इंडिया' तथा घरेलू मूल्य वर्द्धन को भी प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में फेरबदल करने का प्रस्ताव। ■

125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला बजट: नरेंद्र मोदी

संसद में बजट 2018-19 पेश होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला है। ये बजट चौतरफा विकास को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के न्यू इंडिया को मजबूत करने वाला बजट है। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट फार्मर फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली ही नहीं डेवलपमेंट फ्रेंडली भी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग का भी खास ध्यान रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट के जरिए किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दिलवाने की घोषणा करने पर जेटली जी मैं सराहना करता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स एक कारगार कदम साबित होने वाला है। हमने देखा है कि किसी तरह दूध के क्षेत्र में अमूल ने दुग्ध उत्पादन किसानों को उचित मूल्य दिलवाया है। अब सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों को हमारे इस कदम से लाभ मिलने वाला है। देश के अलग-अलग जिलों को ध्यान में रखते हुए वहां के कृषि उत्पादों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्टोरेज बनाने के कदम की भी मैं सराहना करता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा हमारे देश में कॉर्पोरेट सोसाइटीज को इनकम

टैक्स में छूट है। लेकिन एफपीओ जो देश में आज बढ़ रहे उन्हें यह लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब यह लाभ इनको भी मिलेगा। इसलिए किसानों की मदद के लिए जो फारमर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सहकारी समितियों की तरह छूट देने का निर्णय प्रशंसनीय है। ■

बजट 2018-19 पर प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

- यह बजट 125 करोड़ देशवासियों को गति देना वाला है। ये बजट चौतरफा विकास को समर्पित है।
- गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग साढ़े 14 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है।
- मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस का यह बजट है।
- 51 लाख नए घर, तीन लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, बिजली कनेक्शन आदि का सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित लोगों को मिलेगा। इससे नए रोजगारों का सृजन होगा।
- किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी।
- फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है। सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा।
- ऑपरेशन ग्रीन एक कारगर क़दम साबित होने वाला है। आख़िरी छोर पर बैठे लोगों के लिए ये बजट काम का होगा।
- सहकारी समितियों को पहले से ही टैक्स में छूट है, लेकिन अब फ़ॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को भी टैक्स में छूट मिलेगी।
- किसानों और पशुपालकों के फ़ायदे के लिए गोवर्धन योजना लागू की गई है।
- देश अलग अलग जिलों में कृषि उत्पादों को ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। देश के अलग अलग जिलों में एक क्लस्टर योजना बनाई जा रही है। इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया है। इससे अब और प्रकार के लोन किसानों को मिलेंगे।

सर्वांगीण विकास को समर्पित बजट : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत गांव, गरीब, किसान के कल्याण हेतु केन्द्रित और प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट, 2018-19 की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई दी।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के हर बजट की भांति आम बजट 2018-19 भी भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि विकास की कल्पना और विकास, दोनों को देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी और मजदूरों तक पहुंचाने के लिये इस बजट में कई सारी चीजों को समावेशित किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में किसानों की भलाई का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा-नीत मोदी सरकार किसानों के विकास एवं उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों की भलाई के लिये 500 करोड़ रुपये की लागत से 'ऑपरेशन ग्रीन' योजना की शुरुआत की गई है जो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सरकार ने ग्रामीण हाटों के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड़ और राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में संस्थागत कर्ज की राशि को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषि प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए टैक्स राहत की घोषणा से भी इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत सरकार द्वारा 1290 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने से न केवल छोटे किसानों के लिए कृषि के नए विकल्प उपलब्ध होंगे,

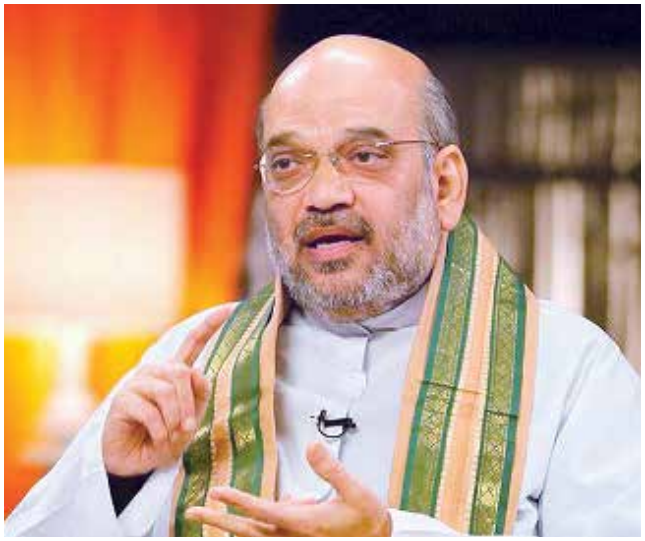

बल्कि बांस-उत्पादों के आयात में भी कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए अलग से दो योजनाओं की शुरुआत हुई है और इसके साथ-साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के सामने 'आयुष्मान भारत' का नया विचार रखा है। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है, जिससे देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाली है, अभी से देश की जनता ने इस योजना को 'नमो केयर' की संज्ञा दे दी है। हमारा मानना है कि यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रावधान इस बजट में किये गए हैं। साथ ही, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है और यह इस बजट से परिलक्षित भी होता है। उन्होंने कहा कि 2022 तक हर आदिवासी क्षेत्र में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया

गया है। उन्होंने कहा कि बड़ोदा में रेलवे यूनिवर्सिटी खुलने से रेलवे सेफ्टी के साथ-साथ रेलवे सेक्टर में रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। साथ ही, स्कूलों को भी मॉडर्नाइजेशन को प्राथमिकता इस बजट में दी गई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए भी कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है और 5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है और अब सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ और शौचालयों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विकास से पीछे रह गए देश के 115 जिलों को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित कर इन जिलों को विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़े जिलों के समकक्ष लाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से इस वर्ष 1.75 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों को ग्रामीण बाजारों और अच्छी सड़कों से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है।

श्री शाह ने कहा कि रेलवे के लिए इस बजट में पिछली वर्ष की तुलना में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीकरण और 4000 किलोमीटर के क्षेत्र के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आम बजट 2018-19 भारत के विकास को सर्वस्पर्शी एवं सर्व-समावेशी बनाने की दिशा की ओर बढ़ाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश की जनता के सामने रखे गए 'न्यू इंडिया' के कंसेप्ट को धरा पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग छः लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही हजारों किलोमीटर नए राजमार्गों का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में हवाई अड्डों की वर्तमान संख्या 124 को लगभग पांच गुना बढ़ाया जाएगा और 'उड़ान' योजना के माध्यम से इसे देश के आम नागरिकों के साथ जोड़ने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किये गए हैं, जो जल-स्तर को ऊपर बनाए रखने में सहायक साबित होगा।

श्री शाह ने कहा कि स्माल एवं मीडियम स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स में कई सारी रियायतें दी गई हैं, जिससे रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी। साथ ही, लघु एवं मध्यम उद्योगों का संरक्षण भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि टैक्सटाइल सेक्टर वेलफेयर के लिए 7,150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो इस सेक्टर की परेशानियों को दूर करने में सफल हो सकेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इससे रोजगार निर्माण में काफी सहायता मिल सकेगी और महिलाओं, ओबीसी, एससी एवं एसटी समुदाय के लोगों को इसका विशेष फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि एससी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ और एसटी वेलफेयर के लिए 39,135 करोड़ अलग से बजट में निर्धारित किये गए हैं। इससे समाज के शोषित एवं वंचित लोगों के कल्याण के साथ-साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले बजट से ही राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है और अब 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट को 3.3% तक सीमित रखने से अर्थव्यवस्था में और मजबूती आयेगी। उन्होंने कहा कि वेतनभोगी वर्ग के कल्याण के साथ-साथ नए रोजगारों के सृजन के लिए मोदी सरकार ने ईपीएफ में मजदूरी का 12% योगदान करने का निर्णय लिया है जो काफी सराहनीय है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आम बजट 2018-19 भारत के विकास को सर्वस्पर्शी एवं सर्व-समावेशी बनाने की दिशा की ओर बढ़ाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश की जनता के सामने रखे गए 'न्यू इंडिया' के कंसेप्ट को धरा पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने अंत में कहा कि मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आज जो लोकाभिमुख बजट प्रस्तुत किया है, यह आने वाले दिनों में भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, इसका हम सबको विश्वास है। ■

कर्नाटक में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 फरवरी को बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत कन्नड़ भाषा में नमस्कार करके किया। उन्होंने जैसे ही कन्नड़ भाषा में नमस्कार कहा, रैली में आए लोगों की भीड़ ने मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए।

कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान रचने का आरोप लगाया और कहा कि इसके सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। श्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस सरकार 'एक्जिट गेट' (निकास द्वार) पर खड़ी है।" श्री मोदी ने सिद्धारमैया सरकार पर कटाक्ष करते हुए इसे 'दस प्रतिशत कमीशन वाली सरकार' करार दिया। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए कहा कि कानून के शासन की जगह, अपराधी शासन चला रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कुछ लोग देश हित की बजाए अपने दल के हित को प्राथमिकता देते हैं। पिछले साढ़े तीन साल में केंद्र से मिलने वाली राशि का लाभ भी कांग्रेस ने लोगों तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में, 1.85 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 34 लाख शौचालय बनाए गए हैं। कर्नाटक में एक करोड़ 16 लाख लोगों का बैंक खाता खुला है। इस राज्य के एक करोड़ लोगों को बीमा योजना को लाभ मिलेगा।

श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बेंगलुरू में एक दिन के लिए बिजली चली जाए तो हाहाकार मच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राज्य के हजारों गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन हमने वहां 7 लाख घरों में बिजली पहुंचाकर लोगों का जीवन रोशन करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, "सरकार ने इस वर्ष देश भर में 9,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाइवे बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतमाला परियोजना के तहत 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपए की लागत राशि से 35 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सरकार देश के 600 बड़े रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम भी हाथ में ले रही है।"

1 फरवरी को संसद में पेश आम बजट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "इस बजट में सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार

ने तय किया है कि विभिन्न कृषि उत्पादों पर, किसानों को लागत की कम से कम डेढ़ गुना राशि अवश्य दी जाएगी।"

उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता किसान हैं। उन्होंने कहा, "फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसान हमारे लिए TOP प्रायरटी पर हैं। TOP यानि Tomato, Onion & Potato, पैदा करने वाले किसानों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई है। दूध के क्षेत्र में अमूल मॉडल बहुत कामयाब रहा वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों के लिए लाभकारी रहेगा।"

उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया में Ease Of Doing Business की बात की जाती है, हमारी सरकार Ease Of Living की बात करती है लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के रहते यहां Ease of Doing Murder की चर्चा होती है। स्थिति ये है कि कर्नाटक सरकार का राजनीतिक विरोध करना भी जान जोखिम में डालने के बराबर है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "विरोध करने वाले को विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, इस से सामाज पर गहरी चोट पहुंची है और इस चोट का जवाब वोट से देना है।" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "PMAY-U के तहत कर्नाटक के लिए अब तक 3 लाख 36 हजार घरों को स्वीकृति दी गई है। लेकिन इसमें से अब तक सिर्फ 38 हजार घर ही पूरे हो पाए हैं। करीब 2 लाख स्वीकृत घरों के लिए तो अब तक काम भी नहीं शुरू हुआ है।"

श्री मोदी ने कहा कि राज्य में 'भगवा लहर' है और कर्नाटक की जनता ने राज्य को कांग्रेस मुक्त बनाने और कांग्रेस संस्कृति से मुक्ति का फैसला कर लिया है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार दस प्रतिशत सरकार है जहां दस प्रतिशत कमीशन दिये बिना कोई काम नहीं होता। अगर यह किसी सरकार की पहचान है तो यह शर्म की बात है।" राज्य पर भ्रष्टाचार के मामले में नया कीर्तिमान बनाने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, "कांग्रेस मुक्त सरकार का मतलब वंशवादी शासन, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और लूट से आजादी है।" उन्होंने राज्य के दो मंत्रियों के आवासों पर आयकर के छापों और एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के छापे में बेनामी संपत्ति के खुलासे का जिक्र किया और कहा, "राज्य में स्टील माफिया, बालू माफिया और तबादला माफिया हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने स्टील पुल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की साजिश रची।

श्री मोदी ने कहा, "जनाक्रोश और भाजपा के प्रदर्शन के कारण परियोजना निरस्त कर दी गई।" वह एक बड़े ट्रैफिक जंक्शन पर शहर में एक स्टील पुल परियोजना का जिक्र कर रहे थे जिसे जनआक्रोश के बाद निरस्त कर दिया गया।

भाजपा और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की हत्याओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाजपा और इससे जुड़े संगठनों के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई।

उन्होंने कहा, "यह सामाजिक ताने बाने पर हमला है। मैं कर्नाटक की जनता से राज्य के सामाजिक ताने बाने पर हमला करने वाली सरकार के खिलाफ वोट देने की अपील करता हूं।" ■

'परिवर्तन यात्रा' रैली पूरे कर्नाटक में एक नवंबर से शुरू होकर 90 दिनों तक चली नवनिर्माण यात्रा के पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई थी। नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन यात्रा को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने दो नवंबर को 224 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाई थी।

सिद्धारमैया सरकार भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण और दमनकारी है: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार को भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण और दमनकारी बताते हुए लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में उसे उखाड़ फेंकने की अपील की। श्री शाह ने 25 जनवरी को मैसूर में पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आपातकाल की तरह ही व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने महादयी जल नदी बंटवारा के मुद्दे पर गोवा के साथ राज्य के विवाद को लेकर आज एक राज्य में बंद का समर्थन करने में कांग्रेस की भूमिका को लेकर उसे आड़े हाथ लिया।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस अब भी वैसा व्यवहार कर रही है, जैसा इसने आपातकाल के दौरान समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस को तैनात कर किया था। साथ ही वह महादयी बंद का आयोजन मेरे और प्रधानमंत्रीजी के परिवर्तन यात्रा संबोधन के समय कर रही है। उन्होंने कहा कि इन हताश कोशिशों के बावजूद कांग्रेस और सिद्धारमैया भाजपा को राज्य में सरकार गठन करने से रोकने में सफल नहीं होंगे क्योंकि कर्नाटक के लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया है।

उन्होंने कहा, "बसें रोकी गयीं , बंद का आह्वान किया गया, चार फरवरी को मोदी जी की रैली को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुझे महान कर्नाटक के लोगों पर भरोसा है।"

उन्होंने कहा, ''मैसूर की इस धरती से, चामुंडेश्वरी देवी की धरती से, कर्नाटक के लोगों को मेरी सिर्फ यह अपील है कि वे भ्रष्टाचारी, दुर्भावनापूर्ण और दमनकारी सिद्धारमैया सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके। उन्होंने सिद्धारमैया सरकार पर वोट की खातिर तुष्टिकरण की राजनीति में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के चलते तीन तलाक विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मुस्लिम बहनों और माताओं को न्याय दिलाने के लिए यह विधेयक पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री शाह ने कहा कि चार साल में भाजपा और आरएसएस के 20 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए हैं। उन्होंने कहा, "मैं सिद्धारमैया सरकार और इसके सभी सहयोगियों से कहना चाहूंगा कि हमारे 20 कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जब भाजपा की सरकार बनेगी, उनके हत्यारे जहां कहीं छिपे होंगे उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा।"

श्री शाह ने मैसूर के 18 वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के सिद्धारमैया सरकार के फैसले को लेकर भी उसकी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि क्या यहां आपमें से किसी की कलाई पर 70 लाख रुपये की घड़ी है? आपके मुख्यमंत्री 70 लाख रूपये मूल्य की घड़ी पहनते हैं। श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में पिछले पांच साल में 3500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। ■

जीएसटी के पहले आठ महीने में अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार के कुशल प्रबंधन और भ्रष्टाचारमुक्त पूर्ण पारदर्शिता के चलते सामान तथा सेवा कर (जीएसटी) के पहले आठ महीने में अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वैच्छिक पंजीकरण में (विशेषतः लघु उद्यमियों द्वारा, जो बड़े उद्यमियों से खरीद करते हैं) काफी वृद्धि हुई है।

अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान करों में राज्यों के हिस्से में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 12.6 प्रतिशत की शुद्ध कर राजस्व (केन्द्र को) की वृद्धि तथा 16.5 प्रतिशत के सकल कर राजस्व से काफी ज्यादा है।

महालेखा नियंत्रक से उपलब्ध नवम्बर, 2017 तक के केंद्रीय सरकार के वित्तीय आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वर्ष 2017-18 के पहले आठ महीनों के दौरान सकल कर संग्रहण पर्याप्त हुआ है तथा गैर-कर राजस्व में धीमी गति के लिए काफी हद तक विनिवेश प्रतिपूर्ति में बेहतर प्रगति हुई है। केन्द्र की प्रत्यक्ष कर वसूली में वृद्धि पिछले वर्ष के अनुरूप रही है और 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ इसके लक्ष्य पर खरा उतरने की उम्मीद है, जबकि अप्रत्यक्ष करों में अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गौरतलब है कि राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात निष्पादन तथा राज्यों के जीवन स्तर के बीच गहरा सम्बन्ध है। दरअसल, भारतीय निर्यात अन्य तुलनात्मक देशों की अपेक्षा बड़ी फर्मों की निर्यातों में भागीदारी बहुत कम है। भारत का आन्तरिक व्यापार जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के सर्वेक्षण में अनुमान से कही अधिक है तथा अन्य बड़े देशों से काफी हद तक बेहतर है। भारत का औपचारिक क्षेत्र, विशेषतः औपचारिक गैर-फार्म पे-रोल इस समय जैसा समझा जाता है, उससे कही अधिक है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से औपचारिक गैर-कृषि कार्यबल के 31 प्रतिशत के लगभग औपचारिक क्षेत्र पे-रोल का अनुमान है, जबकि जीएसटी तंत्र के हिस्से के रूप में औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक क्षेत्र पे-रोल का 53 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

अप्रैल–सितंबर अवधि के दौरान सेवा निर्यात और सेवा आयात में क्रमशः 16.2 एवं 17.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

वर्ष 2017-18 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान सेवा निर्यात और सेवा आयात में क्रमशः 16.2 तथा 17.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र से जुड़ी शुद्ध प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है। सेवा क्षेत्र के शुद्ध अधिशेष (सरप्लस) से वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही के दौरान भारत के विनिर्माण क्षेत्र में दर्ज की गई कमी के लगभग 49 प्रतिशत का वित्त पोषण हुआ।

गौरतलब है कि भारत 3.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वर्ष 2016 के दौरान विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के आठवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपना रूतबा बनाए रखने में कामयाब रहा। यह विश्व में भारत के वाणिज्यिक निर्यात की 1.7 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में दोगुनी है। भारत के सेवा क्षेत्र ने वर्ष 2016-17 में 5.7 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर दर्ज की थी।

सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की अपनी मध्यावधि समीक्षा में भारत

से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप 1140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन सुनिश्चित हुआ है। इससे होटल एवं रेस्तरां, अस्पताल, शैक्षणिक सेवाओं सहित सेवा निर्यात में उल्लेखनीय मदद मिल सकती है। वैसे तो वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्व व्यापार की गति वर्ष 2018 में काफी तेज हो जाने का अनुमान है, लेकिन बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता, संरक्षणवाद और कठोर प्रवासन (माइग्रेशन) नियम भारत के सेवा निर्यात को विशिष्ट आकार देने में महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे। ■

2017-18 के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर पिछले छह सालों में सबसे कम

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर 3.3 फीसदी रही, जो कि पिछले छह वर्षों में सबसे कम है। दरअसल, हाउसिंग, ईंधन और लाइट को छोड़कर सभी बड़े कमोडिटी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर में यह कमी दर्ज की गई। नवबंर 2016 से अक्टूबर 2017 यानी पूरे 12 महीने के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति दर 4 फीसदी से नीचे दर्ज की गई, जबकि चालू वित्त वर्ष अप्रैल-दिसंबर के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसतन करीब एक फीसदी रहा।

यही नहीं, पिछले चार सालों में अर्थव्यवस्था में क्रमिक बदलाव देखा गया, जिसमें एक अवधि के दौरान मुद्रास्फीति काफी ऊपर चढ़ने या काफी नीचे गिरने के बजाय स्थिर बनी रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जरिये मापी जाने वाली प्रमुख मुद्रास्फीति दर पिछले चार सालों में नियंत्रित ही रही है। जाहिर है कि चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में मुद्रास्फीति दर में जो गिरावट देखी गई वह खाद्य पदार्थों में रही। इसकी दर (-) 2.1 से 1.5 प्रतिशत रही। दरअसल, यह कृषि के क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के चलते ही मुमकिन हो पाया है। सरकार ने मूल्यों को लेकर लगातार निगरानी बनाए रखी है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हालांकि हाल के महीनों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में चढ़ाव देखा गया उसकी वजह सब्जी और फलों के दामों में वृद्धि रही है। 2016-17 में ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक खाद्य पदार्थ रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग सेक्टर ने मुद्रास्फीति में मुख्य भूमिका अदा की है। 2016-17 के दौरान यदि हम राज्यवार मुद्रास्फीति की दर देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर राज्यों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बड़ी गिरावट का ही दौर जारी रहा। चालू वित्त के दौरान 17 राज्यों में मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत से कम रही। सरकार की तरफ से कई स्तरों पर किए गए प्रयासों के चलते मुद्रास्फीति दर में यही कमी देखी गई।

2017-18 में किसानों को 20,339 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता

लघु अवधि फसल ऋण पर किसानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज सहायता से उत्पन्न होने वाली विभिन्न देयताओं को पूरा करने के लिए 2017-18 में भारत सरकार द्वारा 20,339 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई। इसके साथ ही फसल कटाई के बाद भंडारण संबंधी ऋण देश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आगत अपेक्षा को पूरा करता है। विशिष्टया छोटे और सीमांत किसान जो कि मुख्य उधार लेने वालों में से है।

यह संस्थागत क्रेडिट किसानों को क्रेडिट के गैर-संस्थागत स्रोत से अलग करने में मदद करेगी। जहां पर यह ब्याज की ऊंची दरों पर उधार लेने के लिए मजबूर होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा, फसलों के ऋण से जुड़ा है। लिहाजा किसान फसल ऋणों का फायदा उठाते हुए सरकार की दोनों किसानों के अनुकूल पहलों से लाभ ले सकेंगे।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि किसान बाजार में अपने उत्पादन के संबंध में लाभदायक कीमतों का लाभ उठाएं, सरकार सुधार को लेकर कदम उठा रही है। इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जो सरकार द्वारा अप्रैल 2016 से आरंभ किया गया था, का उद्देश्य इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिखरे हुए एपीएमसी को एकीकृत करना और किसानों को ऑनलाइन व्यापार करने की सलाह दी जाती है। यह भी अहम है कि वे मान्यता प्राप्त गोदामों में अपने उत्पादन का भंडारण करके फसल की कटाई के बाद ऋण का फायदा उठाएं। यह

हाल के महीनों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में चढ़ाव देखा गया उसकी वजह सब्जी और फलों के दामों में वृद्धि रही है। 2016-17 में ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक खाद्य पदार्थ रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग सेक्टर ने मुद्रास्फीति में मुख्य भूमिका अदा की है।

ऋण ऐसे छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, को 6 माह की अवधि के संबंध में ऐसे भुगतान पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता उपलब्ध है। इसमें किसानों को बाजार में उछाल आने के समय अपनी बिक्री करने और मंदी के दौरान बिक्री से बचने में मदद मिलेगी। अतः छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आवश्यक है कि वे अपने केसीसी को बनाए रखें।

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना चाहती है। इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक सरकार ने तमाम तरह की पहल की है। संस्थानात्मक स्रोतों से क्रेडिट, सभी ऐसे सरकारी प्रयासों जैसे सायल हेल्थ कार्ड, इनपुट प्रबंध, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), PMFBY, E-NAM इत्यादि में पर ड्राप मोर क्रॉप को और बेहतर करेगा। ■

सेवा क्षेत्र की विकास दर 8.3 प्रतिशत

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 55.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का मुख्य घटक रहा और सेवा क्षेत्र के 8.3 फीसदी की दर से वृद्धि करने की संभावना है। 2017-18 में सेवा क्षेत्र में निर्यात के 16.2 प्रतिशत रहा। डिजिटलीकरण, ई-वीजा, लॉजिस्टिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप, हाउसिंग क्षेत्र की योजना सहित कई योजनाएं शुरू की है, जिससे सेवा क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है।

120 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत पहुंचे

संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (दिसंबर 2017) के अनुसार 2016 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन कुल मिलाकर 120 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 करोड़ अधिक रहा। भारत में 2016 में 8.8 मिलियन विदेशी पर्यटक आए। (9.7 प्रतिशत) वृद्धि हुई है और 22.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति हुई (8.8 प्रतिशत) की वृद्धि। वृद्धि के साथ पर्यटन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017 के दौरान 15.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.2 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकि 2016 की तुलना में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

गौरतलब है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए है। हाल ही में उठाए गए कदमों में 163 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटकों/मेडिकल एवं बिजनेस की तीन श्रेणियों के अंतर्गत ई-वीजा की शुरुआत की गई। विभिन्न चैनलों पर 2017-18 के लिए ग्लोबल मीडिया अभियान की शुरुआत भारत में विश्व धरोहर स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए 'द हेरिटेज ट्रेन' भारतीयों का अपने देश के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से 'देखों अपना देश' जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में भारत का शानदार प्रदर्शन

उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। मार्च 2017 में 254 उपग्रहों के के प्रक्षेपण के साथ भारत ने सैटलाइट के क्षेत्र में मिसाल कायम की। इससे भारत को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 2015-16 और 2016-17 क्रमशः 394 करोड़ और 275 करोड़ रुपये का उपग्रह प्रक्षेपण से राजस्व हासिल हुआ। इसी तरह 2014-15 में 149 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ। वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण से प्राप्त होने वाले राजस्व में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इसमें 2015-16 में 1 प्रतिशत की

बढ़ोत्तरी हुई है। 2014-15 में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

अनुसंधान और विकास में भारी वृद्धि

भारत आधारित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सेवाओं में 22 प्रतिशत की वैश्विक बाजार की हिस्सेदारी से 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर एंड डी क्षेत्र में भारत का कुल खर्च जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत है। ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2017 में भारत 127 देशों में 60वें स्थान पर है। 2016 में यह 66th वें पायदान पर था।

सूचना प्रौद्योगिकी–बीपीएम सेवाओं में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि

भारत की सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम में 8.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और नासकॉम के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में 129.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 139.9 बिलियन अमरीकी डॉलर (ई-कॉमर्स तथा हार्डवेयर को छोड़कर) हो गया। आईटी-बीपीएम निर्यातों में 7.6 प्रतिशत वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान यह 107.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 116.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। 2016-17 में ई-कॉमर्स बाजार में 19.1 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ व्यापार तकरीबन 33 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है। गौरतलब है कि अमेरिका-इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन देशों के आईटी-आईटीईएस निर्यातकों ने तकरीबन 90 प्रतिशत का योगदान है। इपेक लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट एशियाई देशों से मांग बढ़ रही है और यूरोप महाद्वीप जापान, चीन, अफ्रीका में विस्तारण के लिए औसत प्राप्त हो रहे हैं।

निर्माण के लिए एकसूत्रता चाहिए

| दीनदयाल उपाध्याय |

समाज की उन्नति का अर्थ क्या है? वैभव का चित्र कौन सा हो, यह कल्पना से रंगा जा सकता है। यदि हमने बुद्धि लगाई तो वैज्ञानिक ढंग से तारतम्य भी बैठाया जा सकता है। कारण मीमांसा भी दी जा सकती है। वास्तविकता यह है कि जीवमान समाज का चित्र कुछ चौखटों में बांधा नहीं जा सकता। सौ वर्ष बाद क्या करेंगे, समाज का क्या चित्र होगा? इसका उत्तर भी वैसा ही है, जैसे बीरबल ने पृथ्वी के केंद्र के संबंध में बताया, पहले तो उन्होंने कहा कि छह महीने की मोहलत और पैसा चाहिए। साथ ही कुछ रस्से और खूंटियां मंगवाकर रख लीं। जंगल में तालाब के बीच में एक खूंटा भी गाड़ दिया और कहा कि यह है पृथ्वी का केंद्र। इसी तरह चौसर खेलने के लिए बैठिए। पचास दांव के हिसाब से गोटी कहां होगी, कहना कठिन है। प्रवृत्तियों का विचार किया जा सकता है। कारण मीमांसा भी दी जा सकती है। किंतु कौन-कौन अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कौन उठेंगे, कहना कठिन है। आज से पचास वर्ष बाद मजदूर, किसान, मिल-मालिक, दुकानदार का क्या संबंध होगा, क्या बनेगा-यह भी कहना कठिन है। भविष्य के बारे में जीवमान समाज का क्या बनेगा, यह भी कहना कठिन है। निर्जीव के लिए तो गति के नियम से हिसाब लगाकर कुछ कहा जा सकता है। ईंट, पत्थर तो चुनकर मकान बनेगा ही। मानव की प्रकृति, प्रवृत्तियां अध्ययन कर बताया जा सकता है। परिणाम सोचे जा सकते हैं। Minutest details नहीं बनाई जा सकतीं।

संगठन और उसके द्वारा वैभव का हमने विचार किया। वैभव की सर्वसाधारण कल्पना छोटी-मोटी रूपरेखा में नहीं हो सकती। हमने अपनी प्रार्थना में उसे व्यक्त भी किया है। परमात्मा से शुभ आशीर्वाद मांगा है। सीधा आशीर्वाद नहीं मांगा।

संगठन और उसके द्वारा वैभव का हमने विचार किया। वैभव की सर्वसाधारण कल्पना छोटी-मोटी रूपरेखा में नहीं हो सकती। हमने अपनी प्रार्थना में उसे व्यक्त भी किया है। परमात्मा से शुभ आशीर्वाद मांगा है। सीधा आशीर्वाद नहीं मांगा। कुछ बातें उसके साथ जोड़ दीं। इस बारे में एक कथा याद आ गई। एक व्यक्ति अंधा होने के साथ-साथ

निर्धन और निसंतान भी था। उसने शिवजी की आराधना की। प्रसन्न होकर प्रभु ने उससे कहा कि एक वरदान मांगो। उसे एक ही वरदान मांगना था। इसलिए उसने सोच-विचार किया कि यदि आंखें ही मांगी तो वह निःसंतान और निर्धन ही रह जाएगा और यदि वह संतान मांग लेता है तो भी वह अंधा और गरीब ही रहेगा, इसलिए उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने पोते को सोने के बरतन में खीर खाते हुए देखूं तो इस तरह उसने समझदारी से सभी कुछ एक ही वरदान में मांग लिया। इसी तरह हमने भी तीन वरदान मांगे कि प्रभु तुम्हारे आशीर्वाद से यह कार्यशक्ति वैभव पर पहुंचाने में समर्थ हों। हमने ताकत से मांगा, कृपा से नहीं। केवल कृपा से जो मिले, वह छिन भी जाता है। भस्मासुर ने भगवान् के सिर पर हाथ रखकर उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन वह उलटा ही हुआ। 'विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्' इसमें अपने वैभव की कल्पना और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों स्पष्ट कर दिए।

जहां पर धर्म नहीं है, वहां पर हमने वैभव ही नहीं माना। धर्म का संरक्षण और वैभव की प्राप्ति दो क्रियाएं हैं। मान लो, बाजार जाकर पुस्तक खरीदनी है। ये दो क्रियाएं हैं। बाजार पहुंचकर पुस्तक खरीदें, यह भी संभव है। यदि क़िताब न मिले या कोई दूसरी खरीद लाएं तो भी ये दो भिन्न-भिन्न क्रियाएं होंगी, लेकिन पानी पीकर प्यास बुझाना, दो भिन्न क्रियाएं नहीं हैं! क्योंकि प्यास तो पानी पीकर ही बुझेगी। बिना पानी पिए प्यास बुझेगी ही नहीं। इसी तरह धर्म का संरक्षण और राष्ट्र

का वैभव दोनों एक साथ हो सकते हैं। धर्म के संरक्षण से ही राष्ट्र का वैभव हो सकता है। ये दोनों बातें अलग नहीं हो सकतीं। धर्म का संरक्षण, राष्ट्र का वैभव और संगठित कार्यशक्ति, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। चोरों में भी अनुशासन, संगठन, त्याग होता है। तस्कर, नाजायज शराब बनाने वालों, जुआ खेलने वालों के भी संगठन होते हैं, लेकिन हमारा संगठन धर्म के आधार पर होता है। समाज और व्यक्ति दोनों का विकास करना चाहिए।

धर्म ही उसका आधार है। इसकी पहली व्याख्या है कि धर्म से ही धारणा हो सकती है। धर्म की अलग-अलग परिभाषाएं हो गई हैं। इसलिए सोचना पड़ेगा कि धर्म क्या है, क्योंकि कोई संस्कृति को लेकर धर्म की बातें करता है और कोई जाति-पाति पर विश्वास करने को धर्म समझने लगता है। हरिजनों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। हरिजनों ने कहा कि भगवान् और भक्त के बीच में कौन बाधक बनते हैं? क्यों बनते हैं? उन लोगों ने धर्म का अर्थ छुआछूत, भेदभाव को समझ

एक-दूसरे में तालमेल और सामंजस्य चाहिए। रेखाओं में से भी सुंदर चित्र बनते हैं। जहां रेखाओं की भरमार हो, वहां साफ किया जाए। केवल विविधता ही होना अच्छा नहीं। बीच में तालमेल भी चाहिए। एक-दूसरे से संबद्ध होकर जब रेखाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं, तभी उस चित्र का विकास होता है। धर्म का काम भी इसी प्रकार है, उसमें भी एकसूत्रता चाहिए निर्माण भी करना है तो भी एकसूत्रता चाहिए।

लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म को छोड़ना ही अच्छा है। एक बार एक अपराधी मामलों के वकील के पास एक सज्जन आए। उन्होंने बताया कि हमने बहुत से बुरे काम किए-डाके डाले, लड़कियां उठाईं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उनसे पूछा गया कि धर्म कैसे नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बताया कि किसी के हाथ का बना भोजन नहीं किया, बिना चौका लगाए नहीं किया। तो धर्म का अर्थ क्या है? यह प्रश्न कठिन है। महाभारत काल में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा कौन सा रास्ता है, जिस पर सब चलें। युधिष्ठिर का उत्तर था, 'धर्म का रास्ता।' लेकिन इसका अर्थ छिपा हुआ है। धर्म के बारे में मतभेद है। कुछ लोगों ने धर्म का अर्थ पूजा-पाठ आदि को ही कहा। मुसलमानों की ओर देखो, उनका एक पैगंबर, एक किताब और एक पद्धति होती है। ईसाई और यहूदी भी ऐसे ही होते हैं। यहां कोई एक किताब नहीं है। वेदों को कोई मानता है, कोई नहीं मानता।

अस्सी प्रतिशत दुनिया तो प्रायः अज्ञानवश ऐसा सोचती है कि यह तो मेरा धर्म नहीं है। आकाश पर सितारे इधर-उधर बिखरे हुए अव्यवस्थित से दीखते हैं। ज्योतिषी तो इन सबकी व्यवस्था को समझता है, किंतु हम नहीं समझ सकते। यह पद्धति है कि हम सबके अनुसार धर्म का अर्थ नहीं लगाते। हमारे यहां विचारों की स्वतंत्रता है, किंतु मुसलमानों में कुरान की बात को ही मानकर चलते हैं। उसके बारे में लिखा है, 'अकल को दखल नहीं'। वहां विचारों में स्वतंत्रता होते हुए भी भेद है। जैसे शिया, सुन्नी इत्यादि। ईसाइयों में कितने चर्च होते हैं। केवल दूर से ही एकता दिखाई देती है। जैसे पहाड़ की एकरूपता दूर से ही नज़र आती है। पास जाकर देखने पर उसमें गहरे खड्ड और खाई नजर आती हैं। हमारा इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। बाकी सभी धर्म तो हमारी तुलना में अभी दुधमुंह बच्चे हैं। सोलह मन्वंतर युग बीत गए। एकरूपता पूरी कैसे नज़र आएगी? यह आश्चर्य की बात है कि इतनी विविधता होते हुए भी हमारे में इतनी एकरूपता है और यही खुशी मनाने का कारण भी है।

एक बार एक गांव का आदमी जो प्याज और गुड़ से ही रोटी खाता था, राजा के यहां से खाने का बुलावा आने पर वहां गया। वहां भोजन देखकर रोने लगा कि यहां तो गुड़ और प्याज है ही नहीं, मैं किससे खाऊं। अतः जहां विकास होता है, वहां विभिन्नता तो होती ही है। प्रथम चरण में अमीबा होता है, उसमें एक ही कोशिका होती है, क्योंकि उसका शरीर गोल-मटोल है। मनुष्य के समान उसके अंगों का विकास नहीं हुआ है। इसलिए उसमें सौंदर्य भी नहीं है। मनुष्य को भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सभी कुछ दी हैं। उसके शरीर में अंगों का विकास हुआ है। अतः उसमें सुंदरता है। यदि उसके भी कान, नाक नहीं होते और वह भी निराकार और बुद्धिहीन होता, उसका विकास न हुआ होता तो उसमें भी सुंदरता नहीं आती।

प्रभुदत्तजी बोलते नहीं, भगवान् का ही नाम बोलते हैं, श्रीकृष्ण कहकर सबको बुलाते हैं, 'हे नाथ' कहकर ही सब खाना-पीना प्रारंभ करते हैं। जैसे एक-दो भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द होते हैं, वैसे ही एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कितने ऊंचे-नीचे स्वर होते हैं। यदि कोई कहे कि अनेक स्वर निकालो, तो मूर्खता होगी। स्वरों में तालमेल चाहिए। अनेक प्रकार के स्वर एक साथ निकलेंगे तो बेसुरा लगेगा। कहीं भी ऊंचा-नीचा किया, contrasting की और सामंजस्य नहीं किया तो सब अटपटा सा लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी पागल के शब्द और उसकी तरह-तरह की आवाजें विचित्र लगती हैं। यह भी विकास नहीं कहलाता। एक-दूसरे में तालमेल और सामंजस्य चाहिए। रेखाओं में से भी सुंदर चित्र बनते हैं। जहां रेखाओं की भरमार हो, वहां साफ किया जाए। केवल विविधता ही होना अच्छा नहीं। बीच में तालमेल भी चाहिए। एक-दूसरे से संबद्ध होकर जब रेखाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं, तभी उस चित्र का विकास होता है। धर्म का काम भी इसी प्रकार है, उसमें भी एकसूत्रता चाहिए निर्माण भी करना है तो भी एकसूत्रता चाहिए। हमारे राष्ट्र की संस्कृति की विविधतामयी प्रकृति में से सामंजस्य का नाम धर्म है। जहां यह एकात्मता हो जाए वहीं धर्म है। नहीं तो विनाश ही होगा। विकृति एकसूत्रता नहीं ला सकती। ■

- संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली (9 जून, 1958)

पालघर सांसद चिंतामन वनगा नहीं रहे

(1 जून 1950 –30 जनवरी 2018)

भाजपा सांसद श्री चिंतामन वनगा का 30 जनवरी को निधन हो गया। श्री चिंतामन को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई।

एक जून 1950 को जन्मे श्री वनगा महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए। वह ग्रामीण विकास और अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय समितियों के सदस्य भी थे। श्री चिंतामन वनगा ने मुंबई विश्वविद्यालय से वकालत तक की पढ़ाई की थी। श्री चिंतामन महाराष्ट्र के थाणे जिले के भाजपा अध्यक्ष भी रहे। 1996, 1999 और 2014 में वो सांसद चुने गए। इसके अलावा चिंतामन महाराष्ट्र की विक्रमगढ़ सीट से विधायक भी चुने गए थे।

प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पालघर के सांसद श्री चिंतामन वनगा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "पालघर के सांसद और

मेरे सहयोगी श्री चिंतामन वनगा की असामयिक मृत्यु से दुखी हूं। उन्होंने ठाणे क्षेत्र में भाजपा की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जनजातियों के कल्याण के लिए सराहनीय काम किया। उनके परिवार जनों और उनके समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने शोक संदेश में कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद चिंतामन वनगा के असामयिक निधन का समाचार जानकर काफी दुखी और स्तब्ध हूं। वे एक उत्कृष्ट नेता, प्रखर समाजसेवी और समर्पित कार्यकर्ता थे। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुये केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि वनगा पार्टी के एक प्रखर कार्यकर्ता थे और उन्होंने ठाणे जिले की जनजातीय पट्टी में शानदार काम किया था। ■

कैराना सांसद हुकुम सिंह का निधन

(5 अप्रैल 1934– 3 फरवरी 2018)

उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री हुकुम सिंह का 3 फरवरी को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। श्री सिंह का निधन नोएडा के जेपी अस्पताल में हुआ। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए ट्विटर पर कहा, ''सांसद और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री हुकुम सिंह जी के निधन से दुःखी हूं। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा की और किसानों के कल्याण के लिए काम किया। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है।''

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि सिंह के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, "कैराना (उत्तर प्रदेश) से भाजपा के सांसद हुकुम सिंह जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। हुकुम सिंह जी का जीवन जनता की सेवा व संगठन को समर्पित रहा, उनका निधन भाजपा परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

जीवन परिचय

श्री हुकुम सिंह जन्म 5 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले स्थित कैराना में हुआ था। श्री हुकुम सिंह पढ़ाई में अच्छे थे। कैराना से उन्होंने 12वीं की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चले गये। वहां से उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। श्री हुकुम सिंह वकालत करते हुए जज की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन उन्होंने देश सेवा के चलते जज की नौकरी ज्वाइन नहीं की। 1996 में हुकुमसिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा की टिकट पर कैराना सीट से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। ■

लोकंतत्र हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 फरवरी को लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि लोकंतत्र हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है, जबकि कांग्रेस ने भारत का विभाजन किया और ऐसा जहर बोया, जिसके कारण आजादी के 70 साल बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता कि उस पाप की सजा सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानी न भुगतते हों। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन का सारांशः

मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें आभार व्यक्त करते हुए कुछ बातें जरूर करना चाहूंगा। करीब 34 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने पक्ष में कहा, किसी ने विपक्ष में कहा, लेकिन एक सार्थक चर्चा इस सदन में हुई। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी दल का नहीं होता है। देश की आशा-आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का और उस दिशा में हो रहे कार्यों का एक आलेख होता है। उस दृष्टि से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कितना उचित है?

हमारे देश में तीन नए राज्यों की रचना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। नेतृत्व अगर दूरदृष्टा हो, राजनीतिक स्वार्थ की हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं होते हों तो कितने स्वस्थ निर्णय होते हैं, इसका उदाहरण तीन राज्यों के निर्माण के समय दिया था, जिसका आज देश अनुभव कर रहा है। जब कांग्रेस दल ने भारत का विभाजन किया और जो जहर बोया, आज आजादी के 70 साल बाद भी एक दिन ऐसा नहीं जाता कि आपके उस पाप की सजा सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानी न भुगतते हों।

लोकंतत्र हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। हाल ही में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा था कि जहांगीर की जगह पर शाहजहां आए, शाहजहां की जगह पर औरंगजेब आए। क्या वहां चुनाव हुआ था, उनके यहां भी आ गए। फिर भी आप लोकतंत्र की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रधान मंत्री ने हैदराबाद के एअरपोर्ट पर एक दलित मुख्यमंत्री को, एक चुने हुए जन प्रतिनिधि को खुले आम अपमानित किया था।

लोकंतत्र हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। हाल ही में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा था कि जहांगीर की जगह पर शाहजहां आए, शाहजहां की जगह पर औरंगजेब आए। क्या वहां चुनाव हुआ था, उनके यहां भी आ गए। फिर भी आप लोकतंत्र की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रधान मंत्री ने हैदराबाद के एअरपोर्ट पर एक दलित मुख्यमंत्री को, एक चुने हुए जन प्रतिनिधि को खुले आम अपमानित किया था।

कांग्रेस पार्टी द्वारा इस देश में 90 से अधिक बार धारा 356 का दरुपयोग करते हुए राज्य सरकारों को हटाया गया। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र में जब आत्मा की आवाज उठती है तो लोकतंत्र को दबोचा जाता है। इस संबंध में श्री नीलम संजीव रेड्डी का उदाहरण स्पष्ट है। इसलिए कृपा करके कांग्रेस हमें लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाए। जब देश में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ तो उस समय पंद्रह कांग्रेस कमेटिया थीं, उसमें से बारह कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था और तीन कमेटियों ने किसी

को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था, उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वह कौन सा लोकतंत्र था? अगर देश के पहले प्रधान मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरे कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास नहीं होता।

क्या कारण था कि पिछली सरकार ने हर रोज 11 किलोमीटर नेशन हाईवे बनते थे, आज एक दिन में 22 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में 80 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं। हमारी सरकार के 3 साल में 1 लाख 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं। पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1100 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ। सरकार के इन तीन वर्षों में 2100 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण हुआ। पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में 2500 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ, इस सरकार के 3 सालों में 4300 किलोमीटर से ज्यादा का काम हुआ।

मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में आज सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी गैस पाइप लाइन, सबसे लम्बा समुद्र के अंदर ब्रिज, सबसे तेज ट्रेन, सारे निर्णय यही सरकार कर सकती है और समय सीमा में आगे बढ़ा रही है। इसी काल खंड में 104 सैटेलाइट छोड़ने का कार्य भी हो रहा है। रोजगारी और बेरोजगारी के आधार पर आलोचना करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि वे जब बेरोजगारी का आंकड़ा देते हैं तो बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का देते हैं। अगर बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का है तो रोजगारी का आंकड़ा भी पूरे देश का होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा और केरल की सरकारों का दावा है कि वहां करीब-करीब एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। क्या आप उनको भी इन्कार करेंगे? सभी जानते हैं कि ईपीएफ में एक साल में 70 लाख नए नाम रजिस्टर हुए हैं और ये 18 से 25 साल के नौजवान हैं, क्या यह रोजगार नहीं है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोन की स्वीकृति हुई है। 10 करोड़ की लोन स्वीकृति में कहीं बीच में कोई दलाल आया, उसकी कोई शिकायत नहीं है। यह इस सरकार के वर्क कल्चर का परिणाम है। इसमें तीन करोड़ लोग बिल्कुल नए उद्यमी हैं। क्या यह भारत की रोजगारी बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके रखी हैं। यह मानसिकता उन्हें वहीं रहने देगी। अस्सी के दशक में 21वीं सदी के सपने दिखाए जाते थे।

21वीं सदी की बात करने वाली सरकार इस देश में ऐवीएशन पॉलिसी तक नहीं ला पाई। हमने एक ऐवीएशन पॉलिशी बनाई और छोटे-छोटे शहरों में जो छोटी-छोटी हवाई पट्टियां पड़ी हुई थीं, उनका हमने उपयोग किया और 16 नई हवाई पट्टियों पर जहाज आना-जाना शुरू हो गया, 80 से ज्यादा एवीएशन के लिए संभावनाएं पड़ी हुई हैं।

चार करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की सौभाग्य योजना हम लाए हैं। वे कहेंगे कि लोगों

चार करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की सौभाग्य योजना हम लाए हैं। वे कहेंगे कि लोगों के घरों में बिजली देने की योजना उनके समय की है, लेकिन 18 हजार गांवों में खम्भे तक नहीं लगे थे और लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हुए थे और वे कह रहे हैं कि यह उनकी योजना है। ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी पिछले तीन सालों में हमने बढ़ायी है।

के घरों में बिजली देने की योजना उनके समय की है, लेकिन 18 हजार गांवों में खम्भे तक नहीं लगे थे और लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हुए थे और वे कह रहे हैं कि यह उनकी योजना है। ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी पिछले तीन सालों में हमने बढ़ायी है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप निर्बाध रूप से बिजली का ट्रांसमिशन करने के लिए नेटवर्क हमने खड़ा कर दिया है। पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए वर्ष 2015 में उज्जवल डिसकॉम एश्योरेंस योजना यानी 'उदय' योजना की शुरुआत की गई है और राज्यों के साथ एमओयू करके इसे आगे बढ़ाया गया है।

बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनियों में बेहतर ऑपरेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित हो, हमने इस पर बल दिया है। घर में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना लांच की गई है। दूसरी तरफ बिजली का काम किया गया है। हमने 28 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे मध्यम वर्ग को लाभ हुआ है। हमने वेस्टेज ऑफ टाइम को भी बचाया है और वेस्टेज ऑफ मनी को भी रोकने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे देश के किसान, जो फसलों का उत्पादन करते हैं, सप्लाई चेन में कमी के कारण ये सम्पदाएं बर्बाद हो जाती हैं। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना शुरू की। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं कि किसान जो भी उत्पादन करता है, उनके लिए रख-रखाव की व्यवस्था मिले। सरकार ने सप्लाई चेन में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए मदद करने का फैसला किया है। ■

हमने पारदर्शी, निर्णायक और संवेदनशील सरकार चलाई है: अमित शाह

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 फरवरी को राज्य सभा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने साढ़े तीन वर्षों के दौरान पचास से ज्यादा ऐसे काम किए हैं, जिनको इस देश के इतिहास में स्थान मिलेगा। इस सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझ-बूझ के साथ विकास करना तय किया। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन का सारांश:

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए: "राष्ट्रपति ने 29 जनवरी, 2018 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्य सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को हम सबके सामने रखा है। इसके विश्लेषण किए जाने का स्वागत है। मगर मैं उसमें एक अलग दृष्टिकोण भी जोड़ना चाहता हूं कि इस सरकार को विरासत में एक प्रकार का गड्ढ़ा मिला, जिसे भरने में ही सरकार का बहुत सारा समय गया है। वर्ष 2013 में देश में हर व्यक्ति को देश के भविष्य की चिंता थी। महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती थीं। सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठौर-ठिकाना नहीं था। सीमा की रक्षा करने वाले जवान सरकार की अनिर्णायकता के कारण अपने शौर्य का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे। युवा आक्रोशित था। घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता चिंतित थी। नीतिगत मामलों में सरकार को लकवा मार गया था। तब 2014 में

इस सरकार ने साढ़े तीन वर्षों के दौरान पचास से ज्यादा ऐसे काम किए हैं, जिनको इस देश के इतिहास में स्थान मिलेगा। इस सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझ-बूझ के साथ विकास करना तय किया और इस क्रम में जो सबसे पहला काम किया गया, वह है जन-धन बैंक एकाउंट खोलने का काम।

चुनाव के दौरान इस देश की महान जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया।

2014 में आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल की सरकार बनी और वह थी श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला कि अपनी पॉलिसी के आधार पर इस देश को आगे ले जाइए। इस देश की समस्याओं का समाधान ढूंढिए। यह जनादेश एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक जनादेश था। मोदी जी को दल का नेता चुना गया और उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा था कि जो सरकार बनने जा रही है वह गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों की सरकार होगी। यह सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर चलकर सभी का विकास करेगी।

इस सरकार ने साढ़े तीन वर्षों के दौरान पचास से ज्यादा ऐसे काम किए हैं, जिनको इस देश के इतिहास में स्थान मिलेगा। इस सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझ-बूझ के साथ विकास करना तय किया और इस क्रम में जो सबसे पहला काम किया गया, वह है जन-धन बैंक एकाउंट खोलने का काम।

70 साल की आज़ादी के बाद 55 साल के कांग्रेस शासन के बाद

भी 60 प्रतिशत लोगों के पास एक भी बैंक एकाउंट नहीं था। मगर आज इस देश में गरीबों के 31 करोड़ बैंक एकाउंट खोले गए हैं। यह टीका-टिप्पणी की गई कि बैंक एकाउंट में जमा करने के लिए गरीबों के पास पैसे कहां से आएंगे, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जन-धन योजना के अन्तर्गत इन खातों में 73 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं।

लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील को सम्मान देते हुए गैस की सब्सिडी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें कुछ और पैसा जोड़कर उज्ज्वला योजना शुरू की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पांच साल में पांच करोड़ गरीब महिलाओं को गैस प्रदान करने का फैसला लिया। अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम पूरा कर लिया गया है और इसी बजट में यह सरकार 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर देने का प्रयास कर रही है।

जहां तक शौचालय के निर्माण का संबंध है, वर्ष 2022 तक हम हर घर में शौचालय की व्यवस्था कर देंगे। घर में शौचालय होने से स्वास्थ्य तो सुधरता ही है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिलता है। हर व्यक्ति को घर देने का स्वप्न भी इस सरकार ने ही देखा है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल हमारी सरकार ने ही ढूंढ़ा। गरीबों के हित के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सका। उनके पास न तो खाते थे, न उनको ऋण मिलता था। ये बेरोजगार युवा दिशाविहीन होकर भटकते थे। आज मुद्रा बैंक के माध्यम से करोड़ों युवाओं को उचित ऋण प्रदान किया गया है। इसमें न गारंटी देनी है, न गारंटर लाना है और ब्याज भी कम रखा गया है।

हमारी सरकार ने साढ़े तीन साल में 18 हजार में से 16 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अस्वस्थ गरीबों के लिए लाई गई हैं। स्टेंट और कृत्रिम घुटने के खर्च को काफी कम किया गया है। इस बजट में 'आयुष्मान भव योजना' लाई गई है जिससे देश की जनता लाभान्वित होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबी हटाने का काम किया है।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री सिचाई योजना अपने आप में विशिष्ट प्रकार की योजना है। इससे पानी की बचत तो होगी ही और कृषि उपज में भी बढ़ोतरी होगी। इस सरकार ने 30 नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम फिर से आरम्भ किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा देश में बहुत सी फसल बीमा योजनाएं लाई गई हैं।

मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' के अंतर्गत उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिन्हें बुआई से लेकर फसल के काटने तक किसी भी आपदा के कारण फसलों का नुक्सान हुआ हो। ब्लाक स्तर पर सर्वेक्षण करने की बजाय अब हर गांव का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 3.5 करोड़ किसानों की मदद के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये गए हैं। समस्त सुविधाओं से युक्त 460 प्रयोगशालाएं इस समय कार्य कर रही हैं और 4,000 छोटी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी किसानों को उनकी फसल पर आने वाली लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देना एक राजनीतिक नारा होता था।

सरकार ने देश की सभी मण्डियों को ई-मण्डी में बदलने की एक योजना बनाई है। 455 मण्डियों को ई-मण्डी में परिवर्तित कर दिया गया है। नीम-कोटेड यूरिया का अन्यत्र उपयोग पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है और इसकी खपत भी कम हो गई है। गोरखपुर, सिन्दरी, बरौनी और तालचर जैसे बंद पड़े उर्वरक कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है। मुझे आशा है कि इस कदम से इस देश में यूरिया को आयात करने की जरुरत नहीं पड़ेगी। डेयरी के लिए 11,000 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई है। जैविक खेती के लिए एक अच्छी पहल की गई है। लगभग साढ़े 22 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 3.5 करोड़ किसानों की मदद के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये गए हैं। समस्त सुविधाओं से युक्त 460 प्रयोगशालाएं इस समय कार्य कर रही हैं और 4,000 छोटी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी किसानों को उनकी फसल पर आने वाली लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देना एक राजनीतिक नारा होता था।

सरकार ने हर फसल के लिए चाहे वह रबी हो या खरीफ, उस पर आने वाली लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। कृषि विकास दर 4.1 प्रतिशत रही है जबकि मुद्रास्फीति 9.5 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई है। ब्याज दर 8 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस', 'ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स, 'ग्लोबल कम्पीटीटिव इंडेक्स इत्यादि के सन्दर्भ में भारत की रैंकिंग में व्यापक सुधार आया है। ■

मुक्त, सर्वसमावेशी और नियम आधारित क्षेत्रीय संरचना के निर्माण पर जोर

भारत-आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन 25 जनवरी को भारत-आसियान संबंधों के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आसियान के दस सदस्य देश जैसे- म्यांमार, थाइलैंड, फिलीपींस, विएतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और मलयेशिया के राष्ट्र प्रमुखों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इन देशों के राष्ट्रप्रमुख, गणतंत्र दिवस की परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में भी शामिल हुए।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत-आसियान के बीच सभ्यता और संस्कृति की समानता का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में मौजूद नेताओं ने भारत-प्रशान्त क्षेत्र में शान्ति, स्थिरता, सामुद्रिक सुरक्षा, आतंकवाद के प्रतिकार, व्यापार और सम्पर्क गहराने की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।

सम्मेलन के अन्त में दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसमें मुक्त, सर्वसमावेशी और नियम आधारित क्षेत्रीय संरचना के निर्माण की बात कही गई। सामुद्रिक सुरक्षा, नौवहन की स्वतन्त्रता, कानून सम्मत सामुद्रिक व्यापार और विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए 1982 के सामुद्रिक कानून यानी यू.एन.सी.एल.ओ.एस. के अनुपालन पर ज़ोर दिया गया। नई दिल्ली ने भारत-प्रशान्त क्षेत्र में मानवीय सहायता, आपदा राहत, सुरक्षा सहयोग और मुक्त नौवहन के क्षेत्रों में अपनी ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दोहराया।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने आसियान के साथ सूचनाओं की साझेदारी, कानूनों के अनुपालन, क्षमता विस्तार, आतंकवादरोधी व्यवस्था में साझेदारी, हवाला कारोबार और आतंकवाद के वित्तपोषण रोकने आदि क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें

भारत-आसियान सहयोग की 25वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन (एआईसीएस) की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने म्यामार की स्टेट कॉउंसलर महामहिम डॉ आंग सान सू ची, वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम श्री न्यूयेन शुआन फुक और फिलीपींस के राष्ट्रपति महामहिम श्री रोड्रिगो रोआ डुटरेट के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें की।

म्यामार की स्टेट कॉउंसलर ऑंग सान सूची के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में परस्पर हित के विभिन्न विषयों, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सितंबर 2017 में म्यामार यात्रा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को आगे बढ़ाने के विषय पर बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री फुक के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक सहयोग के तहत द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के साथ भारत-प्रशान्त क्षेत्र में सामुद्रिक सहयोग, रक्षा,तेल एवं गैस, व्यापार एवं निवेश जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

राष्ट्रपति डुटरेट के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों

भारत और कंबोडिया के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके कंबोडियाई समकक्ष श्री हुन सेन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 27 जनवरी को जल संसाधन विकास की एक परियोजना के लिए ऋण और मानव तस्करी रोकने सहित कुल चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दरअसल, कंबोडिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान ये निम्न समझौते हुए:

- 2018 से 2022 के बीच कंबोडिया के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम। सीईपी के तहत भारत और कंबोडिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन और आपसी संबंधों को सुदृढ़ करना।
- एक्ज़िम बैंक, भारत सरकार और कंबोडिया सरकार के बीच क्रेडिट लाइन समझौता। इसके तहत 36.92 मिलियन डॉलर की स्टंग सवा हब जल संसाधन विकास परियोजना को ऋण मुहैया कराया जाएगा।
- आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहयोग। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों में विधिक सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच अपराध को रोकने, जांच और आपराधिक मामलों में अभियोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।
- आपसी सहयोग के जरिए मानव तस्करी को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन। इसके तहत मानव तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम, मदद और पीड़ितों की स्वदेश वापसी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना।

भारत और कंबोडिया के बीच पुरातन काल से ऐतिहासिक सम्बन्ध: नरेंद्र मोदी

कम्बोडिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस वक्तव्य कहा कि भारत कंबोडिया के पुरातन काल के ऐतिहासिक सम्बन्ध पिछली शताब्दि के उत्तरार्ध में और भी प्रगाढ़ हुए जब कंबोडिया के राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान भारत अपने पुराने मित्र और उसके नागरिकों के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। प्रधान मंत्री हुन सेन और मैं इस बात पर सहमत हैं कि समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार आज हमें अपने सम्बन्धों को हर क्षेत्र में और भी गहरा बनाने की ज़रुरत है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए यह खुशी की बात है कि हमारा मित्र देश कंबोडिया तेज़ी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और पिछले दो दशक में सालाना 7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि हमारे मूल्य और संस्कृति मिलती जुलती है, इसलिए हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में एक स्वाभाविक सिनर्जी हो सकती है।

की प्रगति की समीक्षा के साथ दोनों नेताओं की मनीला में नवंबर 2017 में हुई बैठक के बाद वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों में आये बदलावों की भी समीक्षा की। इस बात पर भी सहमति बनी की दोनों देशों के संबंधों में आयी गतिशीलता को और बढ़ाया जायेगा विशेषकर के आधारभूत सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में।

आसियान–भारत: साझा मूल्य, समान नियति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'आसियान-भारतः साझा मूल्य, समान नियति' के शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में आसियान-भारत साझेदारी के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया। लेख में श्री मोदी ने यह व्यक्त किया कि यह कोई सामान्य आयोजन नहीं है। यह उस उल्लेखनीय यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसने भारत और आसियान को अपने 1.9 अरब देशवासियों यानी दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी के लिए अत्यंत अहम वादों से भरी आपसी साझेदारी के एक सूत्र में बांध दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि आसियान और भारत इसके साथ ही संवाद करने वाले साझेदारों के बजाय अब रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। हम 30 व्यवस्थाओं के जरिए व्यापक आधार वाली आपसी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आसियान के प्रत्येक सदस्य देश के साथ हमारी राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी बढ़ रही है। हम अपने समुद्रों को सुरक्षित और निरापद रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। हमारा व्यापार और निवेश प्रवाह कई गुना बढ़ गया है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत द्वारा विदेश में किए जाने वाले निवेश का 20 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा आसियान के ही खाते में जाता है। सिंगापुर की अगुवाई में आसियान भारत का प्रमुख निवेश स्रोत है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौते अपनी तरह के सबसे पुराने समझौते हैं और किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे महत्वाकांक्षी हैं।

उन्होंने कहा कि हवाई संपर्कों का अत्यंत तेजी से विस्तार हुआ है और हम नई अत्यावश्यकता एवं प्राथमिकता के साथ महाद्वीपीय दक्षिण-पूर्व एशिया में काफी दूर तक राजमार्गों का विस्तार कर रहे हैं। बढ़ती कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप आपसी सानिध्य और ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं, इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया में पर्यटन के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में अब भारत भी शामिल हो गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले 6 मिलियन से भी अधिक प्रवासी भारतीय, जो विविधता में निहित और गतिशीलता से ओत-प्रोत हैं, हमारे लोगों के बीच आपसी मानवीय जुड़ाव बढ़ाने की दृष्टि से अद्भुत हैं। ■

वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2017-18 में 6.75 प्रतिशत होने का अनुमान

आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7-7.5 प्रतिशत रहने के आसार

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 29 जनवरी को संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान किए गए अनेक प्रमुख सुधारों से इस वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़कर 6.75 प्रतिशत और 2018-19 में 7.0 से 7.5 प्रतिशत होगी, जिसके कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पुनःस्थापित होगी। सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि 2017-18 में किए गए सुधारों को 2018-19 में और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

सर्वेक्षण इस बात को रेखांकित करता है कि 1 जुलाई 2017 को शुरू किए गए युगांतकारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार के कारण, न्यू इंडियन बैंकरप्सी कोड के तहत आर्थिक दबाव झेल रही प्रमुख कंपनियों को समाधान के लिए भेजकर, लंबे वक्त से चली आ रही ट्विन बैलेंसशीट (टीबीएस) का समाधान कर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक प्रमुख पुनःपूंजीकरण पैकेज को लागू कर, एफबीआई का और अधिक उदारीकरण कर तथा ग्लोबल रिकवरी से निर्यात को बढ़ाकर वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी और इस वर्ष जीडीपी 6.75 प्रतिशत दर्ज की जा सकती है।

सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया है कि तिमाही अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र की अगुवाई में 2017-18 के दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर में गिरावट की प्रवृत्ति में वापसी सुधार आने लगा। स्थाई प्राथमिक मूल्यों पर ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) में 2016-17 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 6.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसी प्रकार से, 2017-18 में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 2.1 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत दर की वृद्धि होने की उम्मीद है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि दो वर्षों तक नकारात्मक स्तर पर रहने के बावजूद, 2016-17 के दौरान निर्यातों में वृद्धि सकारात्मक स्तर पर आ गई थी और 2017-18 में इसमें तेजी से वृद्धि की उम्मीद जताई गई थी।

सर्वेक्षण में यह वर्णन किया गया है कि भारत को विश्व में सबसे अच्छा निष्पादन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा सकता है, क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत विकास दर वैश्विक विकास दर की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है और उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अधिक है। सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए जीडीपी विकास दर औसतन 7.3 प्रतिशत रही है, जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक है। इस विकास दर को कम महंगाई दर,बेहतर करंट अकाउंट बैलेंस तथा जीडीपी अनुपात की तुलना में वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय गिरावट के चलते हासिल किया गया है जो एक उल्लेखनीय वृद्धि है।

सर्वेक्षण में कुछ देशों में बढ़ते संरक्षणवाद की प्रवृत्तियों के बारे में चिंता जताई गई थी, लेकिन यह देखा जाना है कि स्थिति किस प्रकार रहती है। आने वाले वर्ष में कुछ कारको, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना के कारण जीडीपी विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि 2018 में विश्व विकास दर में मामूली सुधार आने की संभावना के साथ जीएसटी में बढ़ते स्थायित्व, निवेश स्तरों में संभावित रिकवरी तथा अन्य बातों के साथ चालू ढांचागत सुधारों से उच्च विकास दर प्राप्त किए जाने की संभावना है। समग्र रूप से, देश की अर्थव्यवस्था के निष्पादन में 2018-19 में सुधार आना चाहिए।

सर्वेक्षण में यह उजागर किया गया है कि उभरते मैक्रो इकोनॉमिक चिंताओं के संबंध में आने वाले वर्ष में नीतिगत निगरानी आवश्यक होगी, विशेष रूप से जब अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें ऊंचे स्तरों पर बनी रहती हैं या उच्च स्तरों पर स्टॉक मूल्यों में तेजी से गिरावट आती है, जिसके कारण पूंजी प्रभाव में एक अचानक 'सुस्ती' आ सकती है। ■

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा

'हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए'

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 30 जनवरी, 2018 को भाजपा केन्द्रीय कार्यालय 11, अशोक रोड नई दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयन्ती समारोह धूमधाम से मनाया गया। आध्यात्मिक वातावरण में श्री अमित शाह (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा), श्री रामलाल (राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, भाजपा), श्री अरुण सिंह (राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा), श्री विनोद कुमार सोनकर (सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष अ.जा. मोर्चा), श्रीमती कृष्णा राज (केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार), श्री दुष्यन्त कुमार गौतम (पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अ.जा. मोर्चा), श्री वीरेन्द्र कश्यप (सांसद), श्री चिन्तामणि मालवीय (सांसद), श्रीमती अनीता आर्या (पूर्व सांसद व सदस्य एन.डी.एम.सी.) व अ.जा. मोर्चा के पदाधिकारी तथा अनेक गणमान्य नागरिकों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी को पुष्पांजलि अर्पित की।

उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के प्रति सम्पूर्ण समाज पूर्ण श्रद्धा रखता है। वे धर्म और अध्यात्म के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी आजीविका के लिये पैतृक कार्य को अपनाया लेकन उनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने की बजाय सन्त सेवा का माध्यम बना लिया। गुरु रविदास जी ने एक समय अपनी कठौती में ही मां गंगा को बुला लिया था। उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि ''मन चंगा तो कठौती में गंगा'' जोकि आज भी चरितार्थ है। श्री रामलाल ने कहा कि जो सकर्म करते हैं उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो उनके स्थान पर ही उसका सुफल मिल जाता है। श्री रामलाल ने कहा कि सभी को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के आदर्शों व वाणी का अनुसरण करना चाहिये।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए अ.जा.मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि भारत के सभी राज्यों में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयन्ती समारोह मनाया जा रहा है। जिला स्तरों पर भी समारोह मनाने के लिये कहा गया है। मोर्चा के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जाति वर्ग के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, ऐसी योजना व व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। श्री विनोद कुमार सोनकर ने सभी भारतवासियों को श्री गुरु रविदास जयन्ती की शुभकामनाएं दी। ■

आज देश में सामान्य व्यक्ति भी बिना सिफ़ारिश के ऊपर पहुंच सकता है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को वर्ष 2018 के प्रथम 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान कहा कि इन दिनों पद्म-पुरस्कारों के संबंध में काफी चर्चा आप भी सुनते होंगे। अख़बारों में भी इस विषय में T.V. पर भी इस पर ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन थोड़ा अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको गर्व होगा। गर्व इस बात का कि कैसे-कैसे महान लोग हमारे बीच में हैं और स्वाभाविक रूप से इस बात का भी गर्व होगा कि कैसे आज हमारे देश में सामान्य व्यक्ति बिना किसी सिफ़ारिश के उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहें हैं। हर वर्ष पद्म-पुरस्कार देने की परम्परा रही है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में इसकी पूरी प्रक्रिया बदल गई है।

श्री मोदी ने कहा कि अब कोई भी नागरिक किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से पारदर्शिता आ गई है। एक तरह से इन पुरस्कारों की चयन-प्रक्रिया का पूरा रूपांतरण हो गया है। आपका भी इस बात पर ध्यान गया होगा कि बहुत सामान्य लोगों को पद्म-पुरस्कार मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को पद्म-पुरस्कार दिए गए हैं, जो आमतौर पर बड़े-बड़े शहरों में, अख़बारों में, टी.वी. में, समारोह में नज़र नहीं आते हैं। अब पुरस्कार देने के लिए व्यक्ति की पहचान नहीं, उसके काम का महत्व बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राचीन काल से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान, उनका समाज में स्थान और उनका योगदान पूरी दुनिया को अचंभित करता आया है। भारतीय विदुषियों की लम्बी परम्परा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत-सी विदुषियों का योगदान रहा है। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी न जाने कितने ही नाम हैं। आज हम 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करते हैं, लेकिन सदियों पहले हमारे शास्त्रों में,स्कन्द-पुराण में,कहा गया है:-

दशपुत्र, समाकन्या, दशपुत्रान प्रवर्धयन्।
यत् फलं लभतेमर्त्य, तत् लभ्यं कन्यकैकया।।

अर्थात, एक बेटी दस बेटों के बराबर है। दस बेटों से जितना पुण्य मिलेगा एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा। यह हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है और तभी तो, हमारे समाज में नारी को 'शक्ति' का दर्जा दिया गया है।

प्राचीन काल से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान, उनका समाज में स्थान और उनका योगदान पूरी दुनिया को अचंभित करता आया है। भारतीय विदुषियों की लम्बी परम्परा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत-सी विदुषियों का योगदान रहा है। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी न जाने कितने ही नाम हैं।

श्री मोदी ने कहा कि यह नारी शक्ति पूरे देश को, सारे समाज को, परिवार को, एकता के सूत्र में बांधती है। चाहे वैदिक काल की विदुषियां लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी की विद्वता हो या अक्का महादेवी और मीराबाई का ज्ञान और भक्ति हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्था हो या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नारी शक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती आयी है। देश का मान-सम्मान बढ़ाती आई है।

उन्होंने कहा कि हमारी नारी-शक्तियों ने समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए असाधारण उपलब्धियां हासिल की, एक कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने ये दिखाया कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर तमाम बाधाओं और रुकावटों को पार करते हुए एक नया मार्ग तैयार किया जा सकता है। एक ऐसा मार्ग जो सिर्फ अपने समकालीन लोगों को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। उन्हें एक नये जोश और उत्साह से भर देगा।

श्री मोदी ने कहा कि 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्य-तिथि है, जिन्होंने हम सभी को एक नया रास्ता दिखाया है। उस दिन हम 'शहीद दिवस' मनाते हैं। उस दिन हम देश की रक्षा में अपनी जान गवां देने वाले महान शहीदों को 11 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शांति और अहिंसा का रास्ता, यही बापू का रास्ता। चाहे भारत हो या दुनिया, चाहे व्यक्ति हो परिवार हो या समाज-पूज्य बापू जिन आदर्शों को ले करके जिए, पूज्य बापू ने जो बातें हमें बताई, वे आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। वे सिर्फ कोरे सिद्धांत नहीं थे। वर्तमान में भी हम डगर-डगर पर देखते हैं कि बापू की बातें कितनी सही थीं। अगर हम संकल्प करें कि बापू के रास्ते पर चलें -जितना चल सके, चलें- तो उससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

उम्मीदों के प्रावधान

लेकिन अगर हम इस बजट को किसान और गरीब की नजर से देखें, तो यह बजट काफी उम्मीदें बंधाता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना करके किसानों का दिल जीत लेना चाहती है। साथ ही समर्थन मूल्य अब सभी तरह की फसलों पर मिलेगा। सरकार इसकी भी व्यवस्था करना चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों तक पहुंचे। इसके लिए एक तंत्र विकसित करने की भी बात है। अटकल यह है कि शायद इसके लिए मध्य प्रदेश की 'भावांतर योजना' जैसी कोई व्यवस्था बने। लेकिन बजट का सबसे बड़ा फैसला 50 करोड़ लोगों तक स्वास्थ्य बीमा योजना को पहुंचाना है। इसके तहत देश के दस करोड़ परिवार जरूरत पड़ने पर सालाना पांच लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे। बेशक इस फैसले को लोक-लुभावन कहा जा सकता है। जाहिर है कि सरकार अगले चुनाव में इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। इससे भी बड़ा सच यह है कि देश को स्वास्थ्य के लिए ऐसे ही बड़े कदम की जरूरत थी। स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधान बढ़ाकर स्वास्थ्य सुविधाएं सब तक पहुंचाने की बात कई बरस से चल रही है, लेकिन यह कोशिश किसी तरफ जाती नहीं दिखी। योजना से स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर असर न पड़े, इसके लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव भी काफी महत्वपूर्ण हैं।

- (हिन्दुस्तान - २ फरवरी, २018)

वित्त की बुनियाद

आमतौर पर चुनाव के ठीक पहले वाले आम बजट में हर वर्ग के लोगों को खुश करने का प्रयास देखा जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। राजकोषीय घाटे और महंगाई पर काबू पाने तथा औद्योगिक क्षेत्र में बेहतरी लाने की चिंता अधिक दिखाई दी सबसे अधिक जोर कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास पर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में सौ करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को पांच वर्ष के लिए शत प्रतिशत कटौती का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में एक करोड़ घर बनाने का प्रावधान है। इसी तरह रेल बजट में किराया बढ़ोतरी के बजाय रेलवे के संचालन और सुविधाओं में बेहतरी लाने और विस्तारीकरण पर जोर दिया गया है। इसमें सभी पटरियों को ब्रॉडगेज और स्टेशनों को उन्नत तकनीक से लैस करने पर जोर दिया गया है। आज जिस तरह दूसरे क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के उपयोग से बेहतरी लाने का प्रयास दिखाई देता है, रेलवे पिछड़ा नजर आता है, ऐसे में इस बजटीय प्रावधान से कुछ बेहतरी की उम्मीद जगती है। हालांकि लंबे समय से लटकी परियोजनाओं को पटरी पर लाने, गाड़ियों की सुस्त रफ्तारी दूर करने और मुसाफिरों की मुश्किलों को दूर करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इस दिशा में उसे कहां तक कामयाबी मिलती है, इस रेल बजट की सफलता काफी कुछ इस पर निर्भर करेगी।

- (जनसत्ता - २ फरवरी, २018)

याद आया किसान

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों और ग्रामीण क्षेत्र पर रखा। इसे चुनावी बजट कहें या कुछ और लेकिन अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। मुखर तबकों को किनारे रखकर धीरे बोलने वाले नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो थोड़ा जोखिम उठाते हुए सरकार ने इस बार शहरी मध्यवर्ग के बजाय गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी है। संदेश साफ है। जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। किसानों की शिकायत दूर करते हुए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने की बात कही गई है। ऐसे में असल चीज है लागत का सही निर्धारण। सरकार चाहती है कि गांवों में न सिर्फ बुनियादी जरूरतें उपलब्ध हों बल्कि वहां तकनीकी सुविधाएं भी जुटाई जाएं ताकि किसानों का हर स्तर पर विकास हो सके। इसके लिए वहां 2 करोड़ शौचालय बनाने, बिजली और गैस कनेक्शन देने के अलावा गांवों में इंटरनेट के 5 लाख हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे।

- (नवभारत टाइम्स - २ फरवरी, २018)

स्फुट विचार...

पहला मुद्दा क्षेत्रीय असमानताओं और अलग–अलग राज्यों में असमान विकास से जुड़ा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास स्तरों में भी असमानता है। अत: ऐसे उपाय और साधन जुटाने होंगे जिनसे विकास स्तरों पर समानता आ सके ताकि कोई क्षेत्रीय या राज्य यह महसूस न करे कि वह पीछे रह गया या उसे सुविधाओं से वंचित रखा गया।

— कुशाभाऊ ठाकरे

देश एक रहेगा तो किसी एक पार्टी की वजह से एक नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति की वजह से एक नहीं रहेगा, किसी एक परिवार की वजह से एक नहीं रहेगा, देश एक रहेगा तो देश की जनता की देशभक्ति की वजह से रहेगा।

— अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

असम (गुवाहाटी) 'द एडवांटेज असम: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2018' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडिया गेट (नई दिल्ली) पर 'अमर जवान ज्योति' को नमन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बेंगलुरु में परिवर्तन यात्रा रैली के समापन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते कर्नाटक प्रदेश भाजपा नेतागण

नई दिल्ली में आईटीबीपी द्वारा शैक्षणिक भ्रमण पर लाए गए सिक्किम एवं लद्दाख के छात्रों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20